हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 02 सितम्बर, 2024 को माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 2.00 बजे अपराह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

02.09.2024/1400/केएस/वाईके/1

व्यवस्था का प्रश्न

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहता हूं अतः मुझे बोलने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रश्न काल के बाद कर लेते हैं। ...(व्यवधान) मैं आपको प्रश्न काल के बाद अलाउ कर दूंगा। अभी प्रश्न काल होने दें। ...(Interruption) Not allowed. ...(Interruption) क्वैश्चन आवर में प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। परमार साहब, I am not allowing you. ...(Interruption) प्रश्न काल के बाद मैं इजाज़त दे दूंगा। ...(व्यवधान) तभी तो मेरा आपसे आग्रह है कि जब आप इस आसन पर बैठ चुके हैं, तब भी हमारे पास ऐसी कोई कन्वेंशन नहीं है। I am not allowing you Shri Vipin Singh Parmarji. ...(Interruption) आप इसके बाद बोल लेना। ...(Interruption) Nothing will go on record except the Question Hour. We are taking up the Postponed Questions for the day.

02.09.2024/1400/केएस/वाईके/2

प्रश्न संख्या : 1202

अध्यक्ष : श्री पवन कुमार काजल (Not interested)

प्रश्न संख्या : 1610

अध्यक्ष : श्री प्रकाश राणा (Not interested)

प्रश्न संख्या : 1871

अध्यक्ष : श्री बिक्रम सिंह (Not interested)

02.09.2024/1400/केएस/वाईके/3

प्रश्न संख्या : 1872

श्री विनोद सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसके तहत कक्षा-1 में एडमिशन के लिए 6 साल की एज लिमिट का निर्णय लिया गया है। इसमें अभी जो यह transition का पीरियड है, इसमें जो नए स्कूल हैं, उसे ये बहुत rigidly कर रहे हैं। कुछ बच्चों के 6 साल के लिए 10 या 5 दिन रह जाते हैं, मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सिस्टम को अभी हम मर्ज कर रहे हैं, इसको अगर इतना स्ट्राँगली किया जा रहा है तो जो बच्चे हैं उनका एक-एक वर्ष इससे वेस्ट हो रहा है। जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें भी इस तरह की बात आ रही है। मेरा अनुरोध है कि इसके ऊपर सरकार विचार करें जिससे हमारे जो बच्चे जिस क्लास में पढ़ चुके हैं, उन्हें उसे रिपीट न करना पड़े। यह मेरा अनुरोध है।

शिक्षा मंत्री अ0व0 की बारी में---

02.09.2024/1405/av/yk/1

प्रश्न संख्या : 1872--------- क्रमागत

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने अपने लिखित उत्तर में सारी स्थिति स्पष्ट की है। नई शिक्षा नीति के अनुसार आप 6 वर्ष की आयु में क्लास-I में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश अग्रणी प्रदेशों में से एक था जहां पर एन0ई0पी0 को लागू करने की बात की गई थी और यह भी एन0ई0पी0 का एक मुख्य बिन्दु था। हमने इसको पिछले वर्ष लागू करने का निर्णय लिया था। यहां पर माननीय सदस्य श्री विनोद सुल्तानपुरी जी ने जो समस्या बताई है तो इन बातों को देखते हुए हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो बच्चे एनरोल्ड हैं उन्हें पिछले वर्ष व इस वर्ष 6-6 महीने की छूट भी दी गई। परंतु हम इसमें पूर्ण रूप से छूट नहीं दे सकते क्योंकि इससे तो हमारा इस पॉलिसी को लाने का पर्पज़ ही डिफीट जो जाएगा। वर्ष

2006-07 के शैक्षणिक सत्र तक विभाग द्वारा विद्यार्थियों के हित में इस प्रकार की छूट दी गई है।

श्री विनोद सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि कई बच्चे ऐसे हैं जो निश्चित डेट को 6 महीने की छूट देने के बाद भी मात्र 5, 6 या 10 दिन मिस-आउट कर रहे हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बारे में पुनः विचार करके कोई लिबरल व्यू लें ताकि प्रभावित बच्चों को एक रास्ता मिले।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने एन0ई0पी0 में जो 6 महीने की छूट दी है इस बारे में हमने कैबिनेट में पूरी तरह से मनन करके निर्णय लिया है। बाकी तो जैसे मैंने पहले कहा कि हम इसमें पूर्ण रूप से छूट नहीं दे सकते क्योंकि इससे तो हमारा इस पॉलिसी को लाने का पर्पज़ ही डिफीट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें 6 महीने की छूट चलती रहेगी।

प्रश्न संख्या 1873

अध्यक्ष : श्री सतपाल सिंह सत्ती (Not interested)

प्रश्न संख्या 1874

अध्यक्ष : श्री अनिल शर्मा (Not interested)

02.09.2024/1405/av/yk/2

प्रश्न संख्या :1875

श्री नन्द लाल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के माध्यम से जिस सड़क का जिक्र हुआ है इस सड़क में लोक निर्माण विभाग ने काम शुरू कर दिया है और रुकावट भी दूर कर दी गई है। वहां ट्रांसपोर्टेशन के लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट करके एक स्पैन भी लगा दिया है। मैं इसके लिए मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा। मेरा यहां पर यह अनुरोध रहेगा कि इसको हमने पिछले साल विधायक प्राथमिकता में डाला था इसलिए उसकी डी0पी0आर0 इत्यादि तैयार करवाई जाए।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय विधायक ने दियोठी-कुहाल-मुनीष और काशापाठ पंचायत की जिस सड़क के बारे में जिक्र है वह बरसात के दौरान माशनू-तकलेच रोड पर बने सैरी ब्रिज से कट गई थी। यह रोड दिनांक 11.08.2024 को भारी बरसात के कारण कट गया था। इसको विभाग द्वारा तुरंत रिस्टोर किया गया है और यह सड़क अब खोल दी गई है। The road got completely washed away on 11.08.2024 due to heavy rainfall and traffic got hindered due to this but the road was being opened at regular intervals for Light Motor Vehicles. इसका 37 किलोमीटर से 48 किलोमीटर तक का अपग्रेडेशन इन-प्रोग्रैस है।

टी सी द्वारा जारी

02.09.2024/1410/टी0सी0वी0/ए0जी0-1
प्रश्न संख्या : 1875.... जारी
लोक निर्माण मंत्री .... जारी

और इसको प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में अपग्रेड करवाया जा रहा है। इसमें जो अस्थायी रूप से रिटेंनिंगवॉल या रेस्टोरेशन की आवश्यकता है उसको भी विभाग द्वारा पूरा करवाया जाएगा।

प्रश्न समाप्त

प्रश्न संख्या : 1876

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल: (Not interested)

प्रश्न संख्या : 1877

श्री रणवीर सिंह निक्का : (Not interested)

प्रश्न संख्या : 1878

श्री राकेश जम्वाल (सुन्दरनगर): (Not interested)

प्रश्न संख्या : 1879

श्री डी0एस0 ठाकुर (प्राधिकृत डॉ0 जनक राज)**:** (Not interested)

प्रश्न संख्या : 1880

श्री सुरेन्द्र शौरी : (Not interested)

प्रश्न संख्या : 1881

श्री विपिन सिंह परमार : (Not interested)

प्रश्न संख्या : 1882

श्री सुख राम चौधरी : (Not interested)

02.09.2024/1410/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

प्रश्न संख्या : 1883

श्री दलीप सिंह ठाकुर : (Not interested)

प्रश्न संख्या : 1884

श्री आशीष शर्मा : (Not interested)

प्रश्न संख्या : 1885

श्री सुधीर शर्मा : (Not interested)

प्रश्न संख्या : 1886

श्री विनोद कुमार : (Not interested)

प्रश्न संख्या : 1887

श्री दीप राज : (Not interested)

प्रश्न संख्या : 1888

डॉ जनक राजः (Not interested)

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए)

02.09.2024/1410/टी0सी0वी0/ए0जी0-3

प्रश्न संख्या : 1889

Speaker: Whether you want to ask supplementary or not?

सुश्री अनुराधा राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो आर्दश स्वास्थ्य संस्थान खोले जा रहे हैं, इनमें कितने स्पेशल डॉक्टर्ज व सी0एच0ओ0 के पद भरे जाएंगे और इन पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले जा रहे हैं उनमें से दो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान काजा और केलांग में खोले जाएंगे हैं। माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है इसके संदर्भ में मैं इनको बताना चाहता हूं कि लगभग 600 पदों की भर्तियां नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से शीघ्र ही शुरू होने वाली हैं। लाहौल स्पिति में 37 फिमेल हेल्थ वर्कर्ज के पद भरे जा चुके हैं। इसी तरह से काजा और केलांग में भी इन पदों को भर दिया जाएगा। डॉक्टरों के 200 पद कैबिनेट से अप्रूव करवा कर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग

को भरने हेतु भेज दिए गए हैं जिन्हें शीघ्र ही भर दिए जाएंगे। इसके अलावा स्टाफ नर्सिज और अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी को भी शीघ्र ही पूरा कर दिया जाएगा। This infrastructure in Adarsh Swasthya Sansthan will be completed soon.

एन0एस0 द्वारा जारी ...

2-09-2024/1415/एन0एस0-ए0जी0/1

प्रश्न संख्या : 1889 -----क्रमागत

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने काफी स्पष्ट उत्तर दे दिया है। हमारी सरकार हैल्थ सेक्टर में और इंप्रूवमेंट करना चाहती है। आज पिछले पांच सालों में हैल्थ सेक्टर में जितनी कमियां आई हैं हम उनसे निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सभी 68 विधान सभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाए जा रहे हैं। उनमें डॉक्टरों की संख्या भी निश्चित की गई है और अभी हमने 68 विधान सभा क्षेत्रों में 9 स्टाफ नर्सिज सिविल हॉस्पिटल जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों (जो अभी नारे लगाने का काम कर रहे थे) उनके क्षेत्र में भी ओ0टी0ए0 और हर जगह इंस्ट्रूमेंट्स देने का काम शुरू किया है। यह हमारी सरकार की कटिबद्धता है। हमारे हैल्थ इंस्टीच्यूशन्ज में पिछल पांच सालों से बहुत कमियां थीं हम उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ बोलना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जो प्रदर्शन किया है, यह इनका दिवालियापन है। इनका इश्यूज का दिवालियापन है। आज ये रेजोल्यूशन लाए हैं और एक इश्यू दिया है वह आपसे संबंधित दिया है। इनको जनता की फिक्र नहीं है। हिमाचल प्रदेश की जनता के इश्यूज उठाने के लिए सदन में नहीं आए हैं। आज ये आपसे व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। श्री विपिन सिंह परमार जी जो इस माननीय सदन के अध्यक्ष रहे हैं, वे किस प्रकार की बातें कर रहे थे और वह रिकॉर्ड पर नहीं हैं मगर ऐसी बातें करना निंदनीय है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज विपक्ष के माननीय सदस्य यहां पर नहीं हैं। आज इस सदन का पांचवां दिन है। पांच दिन में

किसका एजेंडा लगा है? यहां पर भाजपा के सभी विधायकों का एजेंडा लगा है। आपदा पर जो एजेंडा लगा है वह श्री जय राम ठाकुर जी का इश्यू है। आपने लॉ एंड ऑर्डर दो दिन से लिस्ट किया हुआ है। वह भी इनका इश्यू है। वीरवार को गैर सरकारी कार्य दिवस पर चारों रेजोल्यूशन्ज भारतीय जनता पार्टी के लगे हुए थे। अध्यक्ष महोदय, आपने नियम-61, नियम-62, नियम-63 और नियम-64 में लगभग 10 इश्यूज लगाए हैं और 10 में से 8 इश्यूज इनके लगे हैं। इनको क्या समस्या है? ये इस सदन में चर्चा करने के लिए आते हैं या राजनीतिक

2-09-2024/1415/एन0एस0-ए0जी0/2

ड्रामा करने के लिए आते हैं। आज इनके पास कोई इश्यू नहीं था तो आज यहां ऐसा करने लग गए। नियम-67 में इन्होंने एक रेजोल्यूशन एडजॉर्नमेंट का दिया है। उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इनके दिवालियेपन की हद है कि आज आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, आपके ऊपर अंगुली उठा रहे हैं। ये आपके ऊपर अंगुली उठाना ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। आज इनका नियम-67 का दूसरा रेजोल्यूशन लगा था। उस पर इन्होंने मुंह नहीं खोला, कोई चर्चा नहीं की। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा it is beyond this thing.

प्रश्न काल किसका है और किसके ज्यादा प्रश्न लगे हुए हैं? मेक्सिमम क्वैश्चन विपक्ष के लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विधायकों ने भी प्रदेश की वित्तीय हालत और वित्तीय स्थिति पर नियम-130 में रेजोल्यूशन दिया है और आपने नहीं लगाया है। आपसे गिला-शिकवा सरकार को होना चाहिए। सत्ता पक्ष के विधायकों के इश्यूज तो लग ही नहीं रहे हैं। हमें कोई ऐतराज नहीं है कि किसकी कार्रवाई होगी या आपने किस तरह से संचालन करना है तो वह आपका विशेषाधिकार है। हम उस पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। मगर प्रश्न यह है कि आप इनको जरूरत से ज्यादा अकमोडेट कर रहे हैं। पिछले पांच दिनों में श्री जय राम जी ने 10 प्वाइंट ऑफ ऑर्डर मांगे हैं और आपने 9 प्वाइंट ऑफ ऑर्डर पर अनुमति दी और उन्होंने अपनी बात सदन में रखी। मैंने देखा जब मुख्य मंत्री जी भी जब अपनी बात रखना चाह रहे थे तो आपने प्वाईंट ऑफ ऑर्डर अलाऊ नहीं किया। अलाऊ करना या न करना यह तो आपके अधिकार क्षेत्र में है। They cannot dictate to the Speaker

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

02.09.2024/1420/RKS/AS-1

संसदीय कार्य मंत्री... जारी

कि सदन को कैसे चलाया जाए। आप कभी भी अपनी मर्जी से खड़े होकर बात रखना शुरू कर दें, इस तरह यह सदन नहीं चल सकता। इनका जो वाकआउट है it is a political drama और मैं इसकी निंदा करता हूं।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने यह एक ऐतिहासिक सत्र रखा है। मुझे लगता है कि जब से यह विधान सभा बनी है यह मानसून सत्र पहली दफा 10 दिनों का रखा गया है। यह तय किया गया था कि सत्तापक्ष और विपक्ष के लोग सभी मुद्दों पर इकट्ठा मिलकर चर्चा करेंगे। विपक्ष के लोग जो सवाल करेंगे उनका सत्तापक्ष की ओर से जवाब दिया जाएगा। आपने आज भी चर्चा करने के लिए मना नहीं किया था लेकिन उनकी मंशा कुछ और ही थी। आपने नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करते हुए पिछली बार भी प्रश्न काल से पहले उन्हें व्यवस्था का प्रश्न पूछने की इजाजत दी थी जिसमें उन्होंने ड्रोन से जासूसी के बारे में चर्चा की थी। आज भी आपने बड़ी स्टीक बात कही कि प्रश्न काल होने दीजिए उसके बाद आप अपनी बात रख सकते हैं। प्रश्न काल में भारतीय जनता पार्टी के 10 विधायकों के प्रश्न शीर्ष पर लगे थे। अगर वे प्रश्न काल के बाद अपनी बात रखते तो उसके लिए उन्हें कौन इंकार कर रहा था? लेकिन जिस मंशा से वे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं उसके बारे में हिमाचल की जनता अच्छी तरह जानती है। आप ऐसी मंशा से कितनी बार वाकआउट करेंगे। इन्होंने जो बिना मुद्दे के बात उठाई है आपने उसे रिकार्ड करने की इजाजत नहीं दी है। मुझे लगता है कि विपक्ष के विधायकों की आपसी लड़ाई ज्यादा बढ़ गई है जिस कारण वे तनाव में ज्यादा रहते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने ठीक

कहा कि आज कानून-व्यवस्था और वित्तीय स्थिति जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होनी है और उन्हें इस चर्चा में भाग लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि वे इस चर्चा में खुलकर भाग लेते लेकिन ये लोग इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं जोकि गलत बात है। अध्यक्ष महोदय आपने निष्पक्ष होकर सभी को बोलने का मौका दिया है। आप बोलने के लिए ज्यादा समय विपक्ष के लोगों को ही देते हैं। जब हम अपनी बात कहने के लिए आपकी ओर हाथ खड़ा करते हैं तो हम देखते हैं कि उस समय आपका

02.09.2024/1420/RKS/AS-2

ध्यान विपक्ष की ओर होता है। लेकिन यह आपकी सदन को संचालित करने की कला है और हम आपकी इस कला का विरोध नहीं करते। प्रश्न काल में सभी विधायकों के अपने क्षेत्र व प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लगे होते हैं जिनका जवाब सरकार को देना होता है। जो आपने व्यवस्था दी है कि प्रश्न काल के बाद आप अपने इश्यू पर चर्चा कर सकते हैं, वह सही है; रूलिंग देना आपका ही अधिकार क्षेत्र है। धन्यवाद।

अध्यक्ष : मेरा यह प्रयास रहता है कि जो मुद्दे हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में हों उन्हें चर्चा में लाया जाए। मुद्दे चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष की ओर से उठाए गए हों लेकिन मैं मुद्दों पर चर्चा करने का सभी को पूरा समय देता हूं। विपक्ष द्वारा उठाए गए तथ्यों को चर्चा में इसलिए लाया जाना जरूरी है क्योंकि जब विपक्ष आवाज पैदा करेगा तभी सरकार को उसका जवाब देने का मौका मिलेगा। जो इश्यूज लिस्टिड हैं वे सभी विपक्ष के सदस्यों से संबंधित हैं लेकिन whether they are interested or not interested in the business, that is up to them. सदन की कार्यवाही नियमों के अनुरूप चलती है और जो नियम इजाजत नहीं देता मैं वह व्यवस्था नहीं दे सकता। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो विपक्ष के साथियों ने नियम-274 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वह प्रस्ताव ही नहीं बनता है। It is nowhere in the Rules. I want to tell the Members of the Opposition through you that आप बहुमत से इस सदन

के अध्यक्ष बने हैं। आप कांग्रेस पार्टी के बहमत से स्पीकर बने हैं। Therefore, they have no right to move the resolution. हमारे पास आज भी बहुमत है।

Speaker: There is no such issue under the consideration of the Vidhan Sabha Secretariat as no such issue falls within the purview of the Rules & Procedure of the Vidhan Sabha and under the Constitution also.

अगला प्रश्न 1890 श्री बी.एस.द्वारा....जारी

02.09.2024/1425/बी.एस./ ए.एस-1

प्रश्न संख्याः 1890

श्री भुवनेश्वर गौड़ : अध्यक्ष महोदय, पहला जो मेरा प्रश्न था कि जब सेटलमेंट हुई तो कर्मों से मीटर्ज में इसे बदल दिया गया यह बिल्कुल सही है। दूसरा मेरा प्रश्न है कि कई जगहों पर आबादी में रास्ते बने है और वहां पर लैंड एक्वीजिशन हुई है और जहां पर मकान थे, मकानों का मुआवजा तो लोगों को दे दिया गया है परंतु जो जमीन उनकी वहां पर थी उसका मुआबजा रोका गया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि इन जगहों का मुआबजा क्यों रोका गया है?

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पहले पूछा है वह कोई अन्य प्रश्न है और अभी जो इन्होंने अनुपूरक प्रश्न पूछा है यह कुछ और प्रश्न है। यदि माननीय सदस्य इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो अलग से इसका प्रश्न पूछ सकते हैं और हम उसका विस्तृत जवाब देंगे।

श्री भुवनेश्वर गौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरे से लिखने में गलती हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा।

अध्यक्ष : यदि आप प्रश्न से संबंधित कोई सूचना चाहते हैं तो आप लिख करके दे दीजिए। मंत्री जी उसका जवाब दे देंगे।

श्री केवल सिंह पठानिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री जी ने जानना चाहता हूं कि जो सैटलमैंट की बात आदरणीय भुवनेश्वर गौड़ जी ने रखी है। मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि यह जो सेटलमेंट का रिकार्ड है, यह उर्दू में है। मैं दो दिन पहले शर्मशाला में था और दो- तीन लोग मुझसे सचिवालय में मिले। उन्होंने बताया कि 5-6 और 10-10 हजार रुपये उर्दू पढ़ने वाले ले रहे हैं और छह-छह बार लोगों को कार्यालय में बुला रहे हैं। क्या निकट भविष्य में उर्दू के रिकार्ड को सरकार अपटेड करेगी या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे उस उर्दू के रिकार्ड को पढ़ने के लिए आम जनता को पैसे न देने पड़े।

02.09.2024/1425/बी.एस./ ए.एस-2

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, यह सही बात है कि राजस्व का सारा पुराना रिकार्ड उर्दू में है। वैसे तो हमारे रिकार्ड रूप में हम समय-समय पर लोगों को बुलाते हैं और अगर कोई व्यक्ति अलग से उर्दू पढ़ने वाला बुला करके लाता है और वह कितने पैसे उसको देता है वह उस व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है। परंतु हम यह व्यवस्था जरूर करेंगे कि जहां पर जरूरत पड़े या अनुवाद के लिए जरूरत पड़े तो हम अनुवाद भी करवाएंगे और नया जो रिकार्ड बन रहा है उसमें आसान शब्दावली का प्रयोग किया जाए और हम इसका प्रयास की कर रहे हैं।

श्री भवानी सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, It is just a suggestion. हर जो एन्ड्रॉयड फोन है उसके ऊपर गूगल अनुवाद में उर्दू का अनुवाद मौजूद है। अगर हम इसे परमिट कर दें तो न पैसे की जरूरत रहेगी, क्योंकि आपको इसे एक बार स्केन ही करना है और इसमें अनुवाद हर भाषा की आसान हो जाएगा। अगर सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन आ जाए तो सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है इस पर हम कोशिश करेंगे।

श्री विनोद सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, सेटलमेंट के समय जो गलत हुआ है उसमें मेरे चुनाव क्षेत्र के कुछ क्षेत्र हैं और विशेष कर एक रास्ता जो जाबली में है, वह नेशन हाई वे से एक पोर्सन तक आता है और वह डिसप्ले नहीं हो रहा है और उसकी वजह से disputes arise हो रहे हैं, वह रेलवे फाटक को क्रोस करता है और उसके आगे रास्ता सरकारी दस्तावेजों में है। जो पीछे वाला रास्ता एग्जिस्ट करता है वह अंग्रेजों के समय का रास्ता है वह स्थापित रास्ता है। इस सेटलमेंट के द्वारा वहां रास्ता न होने की वजह से वहां पर लोग रास्ता नहीं बनने दे रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि जब सेटलमेंट हुई है उसके बाद भी अपील करनी पड़ रही है। क्या मंत्री जी इसके ऊपर विचार करेंगे?

Speaker : Hon'ble Minister, it is a suggestion for action.

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

02.09.2024/1430/डी0टी0/डी0सी0-1

प्रश्न संख्या 1890 जारी...

राजस्व मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सेटलमेंट के अपने नियम बने हुए हैं कहीं भी किसी किस्म की कोई शिकायत करनी हो तो नियम के तहत प्रभावित व्यक्ति अपनी शिकायत दे सकता है। लेकिन फिर भी जो माननीय सदस्य ने कहा उसमें हम विचार करेंगे।

02.09.2024/1430/डी0टी0/डी0सी0-2

प्रश्न संख्याः 1891

श्री केवल सिंह पठानियाः अध्यक्ष महोदय, पिछले दिन सरकार ने एक फैसला लिया था ये फैसला बिजली पर सब्सीडी वापिस लेने का था। मैं कहूंगा कि अब वह समय आ गया है कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो माननीय मुख्य महोदय का सपना है उसमें हम सभी को शामिल होना है। चाहे rationalization of educational institutions की बात हो, मुफ्त राशन हो, मुफ्त बिजली हो, मुफ्त पानी हो ऐसे उपभोग की चीजे

आवश्यकता के आधार पर जो व्यक्ति वास्तविक रूप में जरूरतमंद हैं उसे ही देनी चाहिए। एक समय था जब हिमाचल प्रदेश धिरे-धिरे अपने पांव में खड़ा हो रहा था। लेकिन पूर्व सरकार के फैसलों के कारण भी प्रदेश की स्थिति खराब हुई है। पिछली बार जब चुनाव की ओर पूर्व भाजपा की सरकार जा रही थी उस समय बिना बजट प्रावधान के ही कई संस्थान उनके द्वारा खोल दिए गए। आज वह लोग लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं जिन्होंने बजट की बंदर बांट की थी। मैं पहली बार जीत के आया हूं और मैं पिछले पांच दिनों से देख रहा हूं कि विपक्ष सदन की कार्रवाई को कैसे-न-कैसे बाधित करने की कोशिश करता रहा है। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय आपका व सदन के नेता का जिन्होंने हि0प्र0 विधान सभा के इतिहास में पहली बार 10 दिन का मानसून सत्र का आयोजन किया। इसके लिए मैं सदन के नेता और आपको बधाई देना चाहता हूं। ये 10 दिन का सत्र आपके द्वारा इसलिए रखा गया कि जो हिमाचल प्रदेश की 70 लाख आबादी है उनकी समस्या इस सदन में उनके प्रतिनिधियों यानी हम विधायकों द्वारा रखी जायेगी। अगर मैं लोकतांत्रिक परम्पराओं की बात करूं, अध्यक्ष महोदय तो मैं ये अवश्यक कहूंगा कि आप तो विपक्ष का ज्यादा ख्याल रखते हैं क्यों कि आज की कार्यसूची अगर देखें तो सत्ता पक्ष के नौ प्रश्न लगे हुए हैं और विपक्ष के 50 प्रश्न लगे हैं। इस सदन में 26 नए विधायक ऐसे हैं जो पहली बार जीत के इस सदन में आये हैं। हम भी चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई से हम कुछ सीखें। 26 लोग जो हम नए चुन कर आए हैं जब हम कभी अपने संघ की बैठक करते हैं तो सभी सदस्य,चाहे वह सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष, क्योंकि कि संघ तो दोनों ओर के सदस्यों से ही बना है, सभी सदस्य कहते हैं उनमें विपक्ष के भी सदस्य है जिनका नाम मैं यहां नहीं लेना चाहता, कि हमारे प्रश्न लगे होते हैं पर हम प्रश्न नहीं पूछ पाते प्रश्न न पूछ पाने का कारण भी उनको पता है कि वह अपने वरिष्ठ नेताओं के कारण ही प्रश्न नहीं पूछ पाते और उन्हें उनकी सुननी तो पड़ेगी ही। जब नई कक्षा में कोई बच्चा आता है तो टीचर भी उसको ज्यादा बोलने का मौका देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी पर विपक्ष के हमारे साथी जो पहली बार इस सदन के सदस्य बने हैं वह क्या करें ? सदन का

02.09.2024/1430/डी0टी0/डी0सी0-3

अधिकतम समय ऐसी बातों में बीच जाए जो आजकल सदन में हो रही हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम जो 26 नए सदस्य पहली बार इस सदन में चुन कर आए हैं तो उनके संरक्षक माननीय अध्यक्ष जी आप हैं। मैं चाहूंगा कि प्रश्नकाल में जो नए चुने हुए विधायक हैं उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। अब मैं अपने प्रश्न में आऊंगा। जो बिजली सब्सीडी न देने का फैसला सरकार ने जवाब में दिया उससे मु0 1245 करोड़ रुपये का खर्च बचेगा ऐसा आंकलन किया गया। मेरा या माननीय कर्नल धनी राम शांडिल जी या प्रो0 चन्द्र कुमार जी आदरणीय धर्माणी जी का बिल क्यों माफ हो? ये बहुत अच्छी शुरूवात है। इनकम टेक्स हम दे रहें हैं। जब हम किसी रेस्टोरेन्ट में बैठते हैं तो 500/- रुपये निकाल कर टिप वेटर को दे देते हैं। इसलिए मैंने ये प्रश्न किया था कितनी सब्सीडी बनी है। जब मैं शाहपूर में बिजली बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक बैठक ले रहा था तो उन्होंने बताया कि शाहपुर में ही ये राशि 90 करोड़ रुपये होगी। एक महीने का 90 करोड़ रुपया सरकार बचा सकती है। भाजपा वालों ने सोचा था कि हम संस्थान खोल देंगे बिजली का बिल माफ कर देंगे, पानी का बिल माफ कर देंगे तो हम दोबारा सत्ता में आ जायेंगे। लेकिन यह सब कुछ करने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की जनता ने क्या निर्णय दिया वे विपक्ष में पहुंचे हैं और जो विपक्ष में थे वे आज सरकार चला रहे हैं और जिन्हें फिर आने की उम्मीद थी वह आज विपक्ष में बैठें हैं। अगर आप बिना बजट के संस्थान खोलोगे, बिना बजट के आप रेवड़ियां बांटोंगे तो चुनाव के समय हिमाचल की जनता ऐसा ही करेगी । मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं सदन के नेता को कि ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी मुख्य मंत्री ने व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा दिया था उस नारे को सार्थक करने के लिए 18 महीने के अंदर जो कदम उठाए हैं वह हिमाचल के भविष्य के लिए बहुत लाभकारी होंगे और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में सही सिद्ध होंगे।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

02-09-2024/1435/डी.सी.-एन.जी/1

प्रश्न संख्या - 1891.....जारी

श्री केवल सिंह पठानिया.....जारी

जब से हिमाचल प्रदेश की विधान सभा बनी है तब से माननीय सदन के किसी नेता को दोबारा जनता के बीच जाकर मैंडेट लेने का मौका मिला है तो वे माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपके फैसले ठीक थे तभी विधान सभा के 9 उप चुनावों में से 6 में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। सरकार का फैसला पक्ष या विपक्ष के लोग नहीं करते, हमारा फैसला हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता द्वारा किया जाता है। जब हमारी सरकार के 18 माह की कार्य प्रणाली ठीक थी तभी हम 9 उप चुनावों में से 6 उप चुनाव जीत कर आए हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना प्रश्न पूछिए।

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है वह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यह प्रश्न प्रदेश की अर्थव्यवस्था और पिछली सरकार के वित्तीय कूप्रबंधन से भी जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में, जब नवम्बर में चुनाव होने थे तब अप्रैल-2022 में 125 यूनिट तक बिजली को फ्री कर दिया। मतलब यह हुआ कि चुनाव जीतने के लिए चुनावों से 6 माह पहले यह घोषणा की गई। उसके बाद ये लोग (विपक्ष के लोग) फ्री-बीज़ की बात कर रहे हैं और बहुत गला फाड़-फाड़ कर बोल रहे हैं, इसके बारे में इनसे जरूर पूछना चाहिए। इन्होंने तो पानी भी माफ कर दिया था। इन्होंने बिजली, पानी के अलावा भी बहुत कुछ माफ कर दिया लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश की जनता ने 11 दिसम्बर, 2022 को कांग्रेस पार्टी की सरकार बना दी। हिमाचल प्रदेश की जनता द्वारा अपने वर्डिक्ट के माध्यम से कहने का मकसद यह था कि हमें कुछ भी मुफ्त में नहीं चाहिए लेकिन हमें क्वालिटी चाहिए। आज हम क्वालिटी लाइट नहीं दे पा रहे हैं, क्वालिटी फूड नहीं दे पा रहे हैं,

क्वालिटी हैल्थ सर्विस नहीं दे पा रहे हैं और क्वालिटी शिक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं। यह सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने (विपक्ष) अपनी सरकार के समय में लगभग 1000 प्राथमिक पाठशालाएं खोल दीं। हैल्थ के लगभग 300 संस्थान ऐसे खोल दिए जिनमें डॉक्टर्स ही नहीं हैं। मैडिकल कॉलेज और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के ऐसे हालात कर दिए कि एक डॉक्टर यहां से उठाया और एक स्टाफ नर्स दूसरी जगह से उठाई तथा तीसरे स्वास्थ्य संस्थान में नियुक्त कर दिए। हमने इतने वर्षों में जो स्टाफ की स्ट्रैंथनिंग की हुई थी वह भी सारी चरमरा गई। हमारी सरकार ने पाया कि यदि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है तो समाज के सभी वर्गों का साथ चाहिए। चाहे वह कर्मचारी/अधिकारी हो और चाहे हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनसंख्या हो। हमने इस दृष्टिकोण से काम करना शुरू किया। हमने हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सबसे पहला काम बिजली में किया। हमने कहा कि जिस गरीब के पास पैसा नहीं है या है तो बहुत कम पैसा है तो हिमाचल प्रदेश की सरकार उसको पूरी सुविधाएं प्रदान करेगी। हमने जब सब्सिडिज़ का आंकलन किया तो पाया कि 14 प्रकार की सब्सिडी दी जाती हैं। इंड्रस्टीज़ में अलग, कमर्शियल में अलग और लोड के हिसाब से अलग है। मुफ्त में मिल रही 125 यूनिट का गलत उपयोग किया जा रहा है, मान लीजिए जैसे मेरी एक बिल्डिंग है, मैंने उसमें 8 मीटर लगा दिए और उन सभी में 125 यूनिट से कम बिजली उपयोग हो रही है तो पूरी बिल्डिंग की बिजली फ्री हो जाती है। हमने पहला ऐतिहासिक फैसला किया कि हम एक मीटर एक परिवार को देंगे और अभी इस पर काम चल रहा है। मुझे बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रैजंटेशन दी गई और मैंने पाया कि 14 प्रकार की सब्सिडी दी जा रही हैं। जो लोग फाइव स्टार होटल बना रहे हैं, जो कमर्शियल व नॉन कमर्शियल में 5-5 करोड़ या 50-50 लाख आयकर देते हैं, उन्हें सरकार के द्वारा एक रुपया सब्सिडी दी जाती थी उसको हमारी सरकार ने पिछले कल एक सितम्बर से विड्रो कर लिया है। हमने अभी 125 यूनिट फ्री बिजली, जिसे भाजपा ने राजनीतिक तौर पर दिया था, को विड्रो नहीं किया है। हम स्टेज वाइज़ सभी चीजों का अध्ययन करने बाद आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है कि हमें बिजली बोर्ड को भी आत्मनिर्भर बनाना है। बोड्र्स व कॉर्पोरेशन्ज़ के अपने फैसले होते हैं,

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

02.09.2024/1440/केएस/एचके/1

प्रश्न संख्या : 1891 जारी---

मुख्य मंत्री जारी ---

अगर हम सही ढंग से चलेंगे तो वर्ष 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बन सकता है जो कि मैं कई बार कह चुका हूं। जो सब्सिडीज़ दे रहे हैं, इस साल हमें जो बिजली बोर्ड को सब्सिडी देनी है अगर हमने उसमें सुधार नहीं किया तो जो 2200 करोड़ रुपये हमें उन्हें सब्सिडी के रूप में देने हैं, यह कोई कम राशि नहीं है। इसमें से आप 100-150 करोड़ रुपये निकाल लीजिए जो हमने कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में किया। अभी हमने इंडस्ट्रीज़ की सब्सिडी को बंद नहीं किया है, हमने 300 युनिट से ऊपर की बिजली पर सब्सिडी को बंद नहीं किया है, 125 युनिट बिजली की सब्सिडी को बंद नहीं किया है, वन मीटर वन फैमिली भी नहीं किया है। 2200 करोड़ रुपये हमने देने हैं। आप कैसे अच्छी हैल्थ देंगे, कैसे अच्छी शिक्षा देंगे? आज हमारी रेंकिंग क्वालिटी एजुकेशन में 18वें स्थान पर पहुंच गई है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आज बड़े नारे लगा रही है, इन्हें तो यहां आ कर हमारे साथ चर्चा में भाग लेना चाहिए कि हमने कैसे हिमाचल प्रदेश को समर्थ बनाना है। ये राजनीतिक फायदे के लिए ही चर्चा करते हैं, बयान देते हैं। अपने आप तो इन्होंने पांच साल इस प्रदेश के वित्तीय प्रबन्धन का बेड़ा गर्क कर रखा है। ये चर्चा लाएं, हम चाहते हैं कि नियम-130 पर चर्चा हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस मंच के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं कि इन्होंने freebies कर दी और जब हम सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को ओल्ड पैंशन स्कीम देते हैं तो हम सोच समझ कर देते हैं। अगर हम 1500 रुपये देने की बात करते हैं तो सोच-समझ कर करते हैं। इन्होंने तो सब कुछ फ्री कर दिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात आ गई लेकिन बिजली बोर्ड के साथ हम सरकार को भी आत्मनिर्भर करना चाहते हैं। **हम माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। उस सुधार को और आगे बढ़ाकर आने वाले 6 महीने में हम और फैसलों के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब हम अपना अगला बजट प्रस्तुत करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था में आपको सुधार दिखता हुआ नज़र आएगा। धन्यवाद, जय हिंद।**

02.09.2024/1440/केएस/एचके/2

प्रश्न संख्या : 1892

अध्यक्ष : श्री लोकेन्दर कुमार (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या : 1893

अध्यक्ष : श्री पवन कुमार काजल (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या : 1894

अध्यक्ष : श्री बलबीर सिंह वर्मा (अनुपस्थित)

02.09.2024/1440/केएस/एचके/3

प्रश्न संख्या : 1895

श्री मलेन्द्र राजन : अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय लोक निर्माण मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है, पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत हमारे चुनाव क्षेत्र के 6 कार्य सेंक्शन हुए हैं। उनका टेंडर प्रोसैस में है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि 10 सितम्बर, 2024 तक उसको फाइनेलाइज़ कर लिया जाएगा, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ही यह टेंडर प्रोसैस कम से कम 9 महीने लेट हो चुका है तो यह 10 सितम्बर की जो इन्होंने डेट दी है, इसमें यह टेंडर प्रोसैस कम्पलीट हो जाए, यह आश्वासन चाहता हूं और ये जो 6 कार्य हैं, ये जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएं।

इसके साथ-साथ हमारे इंदौरा विधान सभा क्षेत्र की नाबार्ड में विधायक प्राथमिकता में जो हमारी 9 डी.पी.आर्ज़. पैंडिंग पड़ी हैं, उन्हें भी शीघ्रातिशीघ्र टाइम बाउंड फाइनेलाइज़ करवाया जाए।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिस कार्य का माननीय विधायक ने प्रश्न उठाया है, पी.एम.जी.एस.वाई.-3 के तहत जो नूरपुर सर्कल के इंदौरा डिविज़न में कार्य है, नॉन रिस्पांसिव बिड्ज़ की वजह से इसकी टेंडर प्रक्रिया में देरी आई है। इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एण्ड एक्सपेंडिचर सेंक्शन 26.08.2023 को मिल गई थी। Accordingly bids were called by SE 9th Circle HPPWD on 21.01.2024. The technical bids were opened on dated 27.02.2024 and 22 bidders participated in the bidding process for 6 works during technical bids evaluation, none of the bidder qualified technically for opening of financial bids of these works.

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

02.09.2024/1445/av/hk/1

प्रश्न संख्या : 1895--------- क्रमागत

लोक निर्माण मंत्री--------जारी

अभी हमने आपको इसकी 10 सितम्बर, 2024 की डेट दी है। But I cannot give the assurance that work will commence on this date because the bidding process had its own implications. उसमें अगर कोई क्वालिफाई करता है तो the department will go ahead with it. But the delay was not from our side, it is because of non-responsive bids that this delay has occurred.

Second part which the Hon'ble Member has raised about the ongoing NABARD works in his constituency. इसमें कुल 8 रोड्ज हैं जिनकी अभी डी0पी0आर्ज0 बनकर तैयार हुई हैं। इसमें एक सड़क construction of Sahura, Nara,

Brahmna, Tappa road from Km. 0/0 to 4/575 की सड़क है जिसका 15 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इनकी बाकी सात सड़कों की अद्यतन स्थिति अभी भिन्न -भिन्न स्तर पर हैं। इनमें कइयों की डी0पी0आर0 बन रही हैं, कोई एस0ई0 स्तर पर, कोई चीफ स्तर पर तथा कोई नाबार्ड स्तर पर है। ये विभिन्न स्तर पर हैं जिनको हम एक्सपीडाइट करवाएंगे। माननीय विधायक की 150 करोड़ रुपये की राशि एग्जॉस्ट हो चुकी है। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले बजट के दौरान इसमें 25 करोड़ रुपये की राशि और बढ़ाई है। **हम इसको उसके तहत लाने का प्रयास करेंगे तथा आने वाले समय में इसको एक्सपीडाइट करने की कोशिश की जाएगी।**

प्रश्न संख्या : 1896

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या : 1897

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या : 1898

02.09.2024/1445/av/hk/2

श्री चंद्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, इस बार जब सत्र शुरू हुआ था तो मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत इस प्रश्न को उस दौरान भी उजागर किया था। मैंने अभी यह प्रश्न डिटेल में पूछना चाह है और इसमें दो पहलू हैं। इसमें घुमारवीं-सरकाघाट के 41 किलोमीटर रोड को बने 10 वर्ष का समय हो गया है। यहां पर कई बार केंद्रीय मंत्री 50 या 66 नेशनल हाईवे के बारे में बहुत बार बयान दे चुके हैं। परंतु मूल तौर पर सरकाघाट-घुमारवीं रोड हर तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु वांछित सभी मानकों को पूरा करता है। मुझे हैरानी है कि विपक्ष के साथी यहां पर राजनीतिक विषयों के ऊपर वॉकआउट तो करते हैं परंतु जिससे प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को थोड़ा-बहुत सहारा मिल सकता है, उसके ऊपर विपक्ष की तरफ से कोई बयान नहीं दिया जाता। मुझे अपनी माननीय सांसद सुश्री कंगना रणौत सहित, श्री अनुराग

ठाकुर जी जो पांचवी बार सांसद बन चुके हैं और अपने नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी से भी आग्रह करना है जोकि अकसर जिला मण्डी की वकालत करते हैं। परंतु इन्होंने अपने समय में भी और मौजूदा समय में भी हमारे क्षेत्र को पूरी तरह से इग्नोर करके रखा हुआ है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हमीरपुर-टौणी देवी से मण्डी-तलयाड़ तक जिसमें मेरा धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र, माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी का भोरंज, श्री दलीप ठाकुर जी का सरकाघाट और माननीय सदस्य श्री अनिल शर्मा जी का एरिया पड़ता है। यानी उसमें चार महत्वपूर्ण विधान सभाओं का एरिया पड़ता है तथा मेरा उसमें स्टेक ज्यादा है क्योंकि उसमें 140 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर रोड मेरा पड़ता है। अभी मुझे जब गांव-गांव जाने का मौका मिला तो मुझे यह पता चला कि वहां एक आम के वृक्ष हेतु 2000 रुपये का मुआवजा दिया गया।

टी सी द्वारा जारी

02.09.2024/1450/टी0सी0वी0/ए0जी0-1
प्रश्न संख्या : 1898 .... जारी
श्री चन्द्र शेखर .... जारी

जो 20 सालों से फल दे रहा था, वह कौन-सा मापदण्ड था जिसको श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार के समय में वर्ष 2019 में इसके ऊपर लगा दिया गया और उस समय जो बड़ी हुकूमत को चलाने वाले मंत्री हुआ करते थे, वे भी इस विषय पर मौन रहे? लोगों की दुकानें, घर और लगभग 140 पेजों की फेहरिस्त मुझे दे दी गई है जो मेरे किसी काम की नहीं है। मेरा मूल प्रश्न यह है कि आपने जो मुआवजे तय किए वे पूरे हिमाचल प्रदेश में आज तक के इतिहास में सबसे कम मुआवजे हैं और इसकी सजा मेरे और मेरे साथ लगते चार क्षेत्र के लोगों को भुगतनी पड़ रही है। इस विषय की जांच होने चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां सदन में बैठे हुए हैं। किसानों को जमीन का जो मुआवजा मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। मेरा श्री जय राम ठाकुर और उस वक्त के केन्द्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी से यह प्रश्न है। मेरा यह सवाल सांसद,सुश्री कंगना रणौत जी भी है जोकि इस वक्त देश

के किसानों के बारे में ऊलजलूल बोलती है लेकिन हमारे चार विधान सभा क्षेत्र के लोग जो आज त्राहि-त्राहि मचा रहे हैं उनके बारे में उनका एक भी बयान नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच होनी चाहिए और इस नेशनल हाइवे की वजह से बिजली की बहुत बुरी हालत है। हमीरपुर से मण्डी तक बिजली के पोल गिरे पड़े हुए हैं।

दूसरा, ये पाइप लाइनें नहीं बिछाने दे रहे हैं और इसके लिए भारत सरकार से एन0ओ0सी0 भी नहीं मिल रहे हैं। भारत के अंदर यह कैसी सरकार आई है जो एन0ओ0सी0 देने के लिए इनकार कर रही है। पौने 200 करोड़ रुपये की डी0पी0आर्ज0 मंजूर हुई है और उनमें 20-20 प्रतिशत कार्य हो चुका है लेकिन अभी तक पाइप लाइनें बिछाने के लिए मंजूरी नहीं मिल रही है। मैं माननीय सदन के नेता से आग्रह करूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद ।

02.09.2024/1450/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो विषय श्री चन्द्र शेखर जी ने उठाया है, इस विषय पर नियम-62 के तहत भी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। इसकी जानकारी मैं मोर्थ (MoRTH) की ओर से दे चुका हूं लेकिन माननीय सदस्य ने आज प्रश्नकाल में फिर से एक प्रश्न के माध्यम से इस प्रश्न को उठाया है। इस प्रश्न के प्रथम भाग के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकाघाट-घुमारवीं को राष्टीय मार्ग से नेशनल हाईवे बनाने की मांग वर्ष 2016-17 में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा की गई थी। इसका विस्तारीकरण का कार्य विश्व बैंक परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दो लेन के मानकों के अनुसार किया गया गया है। सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2016-17 में पत्र दिनांक 14-09-2016 द्वारा प्रदेश की 69 सड़कों की सांविधानिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया था जिसमें यह सड़क भी शामिल है। मैं पहले भी इस विषय को कई बार सदन में ला चुका हूं। आज फिर से इस विषय के बारे में बताना चाहता हूं कि ये 69 नेशनल हाइवेज वर्ष 2017 में तत्कालीन और वर्तमान केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री द्वारा अनाउंस किया गया था लेकिन इन 69 नेशनल हाइवेज को अब 25 करने के साथ उन्होंने निवेदन किया है। उसके बाद इनको फिर से करटेल करके प्रदेश सरकार की ओर से 6 सड़कों को अपग्रेड करने का मोर्थ से निवेदन किया है लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार को उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है जिस सड़क का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है

इसको भी सरकार की ओर से भेजा गया है। इसका जो दूसरा भाग है जिसके बारे में इन्होंने जानकारी प्राप्त करने का निवेदन किया है, इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग -70 हमीरपुर से मण्डी 141 से 265 तक के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण किया गया है व उसका मुआवजा भी प्रदान किया गया है।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

2-09-2024/1455/एन0एस0-वाई0के0/1

प्रश्न संख्या : 1898 -----क्रमागत

लोक निर्माण मंत्री ----- जारी

जिसमें निजी 201 करोड़ रुपये है और सरकारी भूमि में 93.6 करोड़ रुपये है। लगभग कुल 295 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग-70 हमीरपुर से मण्डी के निर्माण हेतु अधिकृत भूमि का मुआवजा Right to Fair Compensation Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 की धारा-26 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित कर संबंधित मुहाल की भूमि औसत बाजारी मूल्य व जिला समहर्ता द्वारा उस वर्ष के निर्धारित सर्कल रेट जिसमें जो भी उच्चतम पाया गया है, के अनुसार उच्चतम मूल्य पर निर्धारित किया गया है तथा इस मूल्य पर उक्त अधिनियम की धारा-30 के प्रावधानों के अंतर्गत शत प्रतिशत Solatium दिया गया है तथा भूमि की मूल मुआवजा राशि पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनिश्म, 1956 की धारा 3 ए जारी होने की तिथि से अवार्ड की घोषणा की तिथि तक बने कुल दिनों पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया गया है। अधिग्रहित सरकारी भूमि के लिए कोई मुआवजा देय नहीं है।

अंत में माननीय सदस्य ने बिजली के खंभे के बारे में और पानी की पाइपों की डेमेजिज के बारे में पूछा है और इसका उत्तर मैंने पिछली बार भी दिया है on behalf of MoRTH कि इसके लिए उन्होंने संज्ञान लिया है और बजटरी प्रोवीजन करवाया गया है। जहां पर भी रेस्टोरेशन दोनों का होना है उसको प्राथमिकता से करवाया जा रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपका धन्यवाद, जय हिंद।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

2-09-2024/1455/एन0एस0-वाई0के0/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने विस्तृत उत्तर दिया है। पिछले दिनों हम दिल्ली गए थे तब मंत्री जी भी साथ गए थे। माननीय चंद्र शेखर जी ने जो मोर्थ की बात कही है तो मंत्री जी ने उस विषय को उठाया भी था और मैंने भी इस बात को उठाया था। अब यह बड़ी विडम्बना है कि मंत्री जी के विभाग के अंदर केंद्रीय मंत्री के मोर्थ का काम आता है। मैं वहां पर व्यक्तिगत तौर पर खुद गया हूं और साथ में मंत्री जी व चंद्र शेखर जी खुद भी गए। यह देखा गया कि इस काम की स्पीड बहुत स्लो है और कोस्ट एस्केलेशन कितनी बढ़ गई

होगी और वह भी स्लो है। इस सब की रिपोर्ट हमें चाहिए तो **मैं इसके लिए आश्वासन देना चाहता हूं कि हम सेक्रेटरी लैवल की कमेटी बना कर पूरी रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और फिर आगे जैसे बढ़ना होगा हम देखेंगे तथा आगे बढ़ेंगे।**

2-09-2024/1455/एन0एस0-वाई0के0/3

प्रश्न संख्या : 1899

श्री विवेक शर्मा (विक्कू) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मेरे विधान सभा क्षेत्र कुटलैहड़ से संबंधित है। इस बार जो खैर का कटान हुआ तो सरकार को खैर के कटान से 15 से 18 करोड़ रुपये का फायदा हुआ। अध्यक्ष महोदय, पहले जो कटान होता था उस वृक्ष का नम्बर अंकित होता था और जमीन से एक या डेढ़ फुट ऊपर कटान किया जाता था। मगर आज कटान कटर के साथ किया जाता है और जड़ से पेड़ को उखाड़ा जा रहा है। मेरा मानना है कि कुटलैहड़ से खैर का ज्यादा पैसा आया है और एक अच्छी क्वालिटी का खैर पाया जाता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कुटलैहड़ के जंगलों में ज्यादा-से-ज्यादा खैर लगाए जाएं और किसानों को खैर के पेड़ की राशि निर्धारित की जाए ताकि उनको फायदा हो। इसके अतिरिक्त जो जड़ से खैर के पेड़ को उखाड़ा जा रहा है उसको जड़ से न उखाड़ा जाए ताकि खैर दोबारा से उग सके।

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

02.09.2024/1500/RKS/AG-1

प्रश्न संख्याः 1899... जारी

श्री विवके शर्मा (विक्कू) जारी

क्योंकि आरे से काटने पर खैर का पेड़ दोबारा नहीं उगता। सरकारी भूमि पर जो खैर के पेड़ लगे हुए हैं और पीछे अवैध कटान का बड़ा मुद्दा कुटलैहड़ में भी उठा था जहां जंगलों के जंगल साफ कर दिए थे। मैं चाहता हूं कि विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों को कुछ शक्तियां दी जाएं ताकि वे मौके पर दोषियों को पकड़कर सजा दे सकें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि पहले खैर का स्टम्प आधा, पौना या एक फुट रह जाता था। खैर के पेड़ की मोटाई के हिसाब से किसान को पैसे दिए जाते हैं। माननीय सदस्य ने जो बात मेरे ध्यान में लाई है मैं उस संबंध में अधिकारियों से बात करूंगा और इसमें जो चीजें आगे करनी होंगी उन्हें किया जाएगा।

प्रश्न काल समाप्त।

02.09.2024/1500/RKS/AG-2

अध्यक्ष : इससे पहले कि मैं दूसरी आइटम लूं मैं आपको कहना चाहूंगा कि नियम-67 के अंतर्गत दोपहर 12.46 बजे सर्वश्री जय राम ठाकुर, रणधीर शर्मा, सुख राम चौधरी, विपिन सिंह परमार, सुधीर शर्मा एवं सतपाल सिंह सत्ती से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जोकि आज सितम्बर माह की 2 तारीख होने के बावजूद कर्मचारियों के वेतन व पेंशनर्ज को पेंशन न मिलने के कारण आर्थिक दीवालियापन से संबंधित हैं। दिनांक 28.08.2024 को इसी विषय पर सर्वश्री केवल सिंह पठानिया, चंद्र शेखर व श्री भवानी सिंह पठानिया, माननीय सदस्यों से नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जोकि प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति पर सदन चर्चा करें से संबंधित है। इस प्रस्ताव को आगामी कार्रवाई हेतु सरकार को प्रेषित किया जा चुका है तथा सरकार से भी इसका उत्तर प्राप्त हो गया है। इस प्रस्ताव पर इसी सत्र में नियम-130 के अंतर्गत चर्चा करवाई जा सकती है और यह प्रस्ताव

चर्चा के लिए लिस्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं संचालन नियमावली के नियम-69 सब रूल-6 के अंतर्गत the motion shall not anticipate a matter, which has been previously appointed for consideration. In determining whether a discussion is out of order on the ground of anticipation, regard shall be held by the Speaker to the probability of the matter anticipated being brought before the House within a reasonable time. अतः इस स्थगन प्रस्ताव को अविलंब चर्चा करवाने का कोई औचित्य नहीं रहता यद्यपि जिन्होंने यह प्रस्ताव यहां लाया है वे भी इस माननीय सदन में नहीं है। Therefore, I am rejecting this Motion and we will discuss it under Rule 130 later. माननीय राजस्व मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

02.09.2024/1500/RKS/AG-3

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने वैसे तो व्यवस्था दे दी है लेकिन मेरा यह कहना है कि नियम-67 को तभी लाया जाता है जब कोई अर्जेंट या स्पेसिफिक विषय हो। आज हमारे विपक्ष के सदस्य प्रश्न काल से पहले किसी और मुद्दे को लेकर यहां आ गए उससे यह मालूम होता है कि नियम-67 केवल दिखावे के लिए लाया गया था। इस नियम को लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसका मतलब यह हो गया कि नियम-67 को जान-बूझकर सोसे के लिए लाया गया था। इससे यह साफ झलकता है कि विपक्ष वालों को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि महत्वपूर्ण यह वाला विषय है या जो श्री विपिन सिंह परमार जी उठा रहे थे वह वाला है। अध्यक्ष जी, वैसे तो नियम-67 ऑटोमेटिकली गिर चुका है लेकिन दोबारा इस तरह का मामला आता है तो उन्हें एक बार समझाना पड़ेगा कि नियम-67 में सारे काम को छोड़कर सिर्फ उसी विषय पर चर्चा करनी होती है जिसे नियम-67 के अंतर्गत लाया गया हो।

अध्यक्ष : मेरा भी यही कंसर्न था कि नियम-67 में प्रस्ताव लाने के बाद उसका उल्लेख न करना और तरह-तरह की बातें करना जिसका संबंध माननीय सदन के अंदर हुई चर्चाओं

से नहीं है और न नियमों के अनुरूप है। इससे the seriousness of the Opposition रिफलैक्ट होती है। जैसा मैंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी सत्तापक्ष से ज्यादा है।

श्री बी.एस.द्वारा....जारी

02.09.2024/1505/बी.एस./ ए.जी-1

अध्यक्ष जारी...

क्योंकि वे सत्ता में पांच वर्ष तक रहे हैं इसलिए उनको पिछले पांच वर्षों का जवाब भी देना है और वर्तमान सत्ता के अन्दर उन्हें लगता है कि कहीं कोई कमी रही है तो उसके सुधार हेतु भी उन्हें यहां पर सुझाव देने हैं। I don't think they are concerned about the Himachal Pradesh issue.उद्योग मंत्री जी आप क्या कहना चाहते हैं?

उद्योग मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जी ने बहुत ठीक कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के दिवालियापन की स्थिति है। आप अध्यक्ष महोदय को नियम-67 के अन्तर्गत एक नोटिस दे रहे हो, लेकिन सदन में आप न उसकी चर्चा कर रहे हैं और न उसकी मांग कर रहे हो। आप दूसरा ही कोई इश्यू ले करके आ गए हैं और उस पर आप चर्चा करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने उस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी।

Speaker: We have not taken a cognizance of that.

02.09.2024/1505/बी.एस./ ए.जी-2

Parliamentary Affairs Minister: But they were not serious regarding the Adjournment Motion. अध्यक्ष महोदय, यहां पर ये चर्चा कर रहे थे। मैंने खुद नेता प्रतिपक्ष जी से टेलीफोन पर बात की थी। मैंने इनके मुख्य सचेतक आदरणीय सुख राम चौधरी जी से भी बात की भी। अगर मुख्य मंत्री जी ने इस सत्र को 10 दिन के लिए रखा है तो इसलिए रखा है कि प्रदेश के इश्यूज को सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य सदन में रखें और सरकार उसका जवाब देने को तैयार है। हिमाच प्रदेश के इतिहास में अध्यक्ष

महोदय, पहली बार कोई मानसून सत्र 10 दिनों तक के लिए रखा गया है। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि पंजाब का मानसून सत्र केवल तीन दिन के लिए रखा गया है। लेकिन 10 दिन के सत्र के लिए भी विपक्ष के लोग भाग रहे हैं। आज अभी चर्चा का उत्तर मंत्री जी ने देना है। इन्होंने शुक्रवार को चर्चा का उत्तर देना था परंतु मेरे आग्रह पर आपने उसे डेफर करके सोमवार को किया कि सोमवार को विपक्ष के माननीय सदस्य सदन में आएंगे। इन्होंने यदि कोई अनुपूरक प्रश्न पूछना है या कोई स्पष्टीकरण लेना है उसे ले सकते हैं परंतु आज फिर से ये सदन से बाहर चले गए हैं। यह बिल्कुल भी चर्चा के लिए गंभीर नहीं है और यह समय की बर्बादी है। आपने ठीक कहा कि सदन को चलाने की जिम्मेवारी केवल सरकार कही नहीं है। आदरणीय विपक्ष के नेता इस प्रदेश के बहुत-बड़े नेता रहे हैं और ये पूर्व में मुख्य मंत्री रहे हैं इनकी भी जिम्मेवारी है। मैंने कल भी इनसे बात की और आग्रह किया कि जो आपके इश्यूज हैं उन्हें हम बैठ करके सुलझा सकते हैं। आपको उचित समय दिया जा रहा है और आपकी बात को सुना जा रहा है। मगर one sided affairनहीं चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जब-जब ये बोलने के लिए उठेंगे तब-तब आप अनुमति देंगे। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि सरकार इतनी कमजोर नहीं है। सरकार ने कोई गलत कार्य नहीं किया है, सरकार हिमाचल प्रदेश के हित में है और मुख्य मंत्री जी हिमाचल प्रदेश के हित में कार्य कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और संपन्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष सरकार का सहयोग देगा।

02.09.2024/1505/बी.एस./ ए.जी-3

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री,सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जोकि इस प्रकार है :-

सोमवार 02 सितम्बर, 2024 : 14.00 बजे (अपराह्न)
शासकीय/विधायी कार्य

मंगलवार 03 सितम्बर, 2024 : शासकीय/विधायी कार्य

बुधवार, 04 सितम्बर, 2024 : शासकीय/विधायी कार्य

वीरवार, 05 सितम्बर, 2024 : (1) शासकीय/विधायी कार्य

(2) गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस

शुक्रवार, 06 सितम्बर, 2024 : शासकीय/विधायी कार्य

शनिवार, 07 सितम्बर, 2024 : बैठक नहीं होगी।

रविवार, 08 सितम्बर, 2024 : अवकाश।

02.09.2024/1505/बी.एस./ ए.जी-4

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्या 35) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, शिमला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24; और
ii. संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमऊर्जा (हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अभिकरण) हिमाचल प्रदेश का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24।

अध्यक्ष : अब उद्योग मंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, संयुक्त निदेशक, ग्रुप-ए (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम (प्रथम संशोधन), 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः इन्ड-ए(ए)3-6/2023, दिनांक 16.02.2024 द्वारा

अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.02.2024 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेगें।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, संयुक्त निदेशक, ग्रुप-ए (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम (प्रथम संशोधन), 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः इन्ड-ए(ए)3-6/2023, दिनांक 16.02.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.02.2024 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब नगर और ग्राम योजना मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

02.09.2024/1505/बी.एस./ ए.जी-5

नगर और ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्याः टीपीटी-ए(3)-4/2013-I, दिनांक 10.11.2023 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.11.2023 को प्रकाशित; और

(ii) हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 3-ग की उप-धारा (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा हिमाचन प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 से संलग्न अनुसूची-III के संशोधन, जोकि अधिसूचना संख्याः टीपीटी-ए(3)-7/2019-II, दिनांक 06.01.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.01.2024 को प्रकाशित।

02.09.2024/1505/बी.एस./ ए.जी-6

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। श्री नन्द लाल सभापति, कल्याण समिति, कल्याण समिति के प्रतिवेदनों की प्रति एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री नन्द लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(i) समिति के 25वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (2020-21) पर बने 38वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (2021-22) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन योजना से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के 15वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (2019-20) पर बने 29वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (2020-21) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम तथा समेकित बाल संरक्षण योजना से सम्बन्धित है।

02.09.2024/1505/बी.एस./ ए.जी-7

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों की पुरः स्थापना

अध्यक्ष : अब कृषि मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 25) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 25) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 25) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 25) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई।

अब कृषि मंत्री हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 25) को पुरःस्थापित करेंगे।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 25) को पुरःस्थापित करता हूं।

02.09.2024/1505/बी.एस./ ए.जी-8

अध्यक्ष : "हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 25) पुरःस्थापित हुआ।"

अध्यक्ष : अब नगर और ग्राम योजना मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

नगर और योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 5)को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 5)को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब नगर और ग्राम योजना मंत्री हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करेंगे।

नगर और ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 25) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : " हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 5) पुरःस्थापित हुआ।"

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

02.09.2024/1510/डी0टी0/ए0एस0-1

नियम-130 के अंतर्गत दिनांक 27.8.2024 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे चर्चा

अध्यक्षः अब नियम-130 के अंतर्गत जो चर्चा इस माननीय सदन में 27.8.2024 से चल रही है उस चर्चा पर आगे विचार-विमर्श होगा। मेरे पास सत्ता पक्ष की ओर से 5 माननीय सदस्यों के नाम आ चुके हैं और मैं एक-एक करके उनके नाम लूंगा and we will try to conclude this disucssion today and we will take up the next issue today जो नियम-130 के अंतर्गत कानून-व्यवस्था पर माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल, माननीय सदस्य श्री बलवीर सिंह वर्मा, माननीय सदस्य श्री सुख राम चौधरी द्वारा दिया गया है। Hopefully they may return. अब माननीय श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मंत्री 27.8.2024 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा को आगे बढ़ायेंगे।

लोक निर्माण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सदन में जो प्रस्ताव नियम-130 के अंतर्गत दिनांक 27.8.2024 को प्रस्तुत किया गया है "प्रदेश में भारी बरसात/आपदा के कारण जनमानस, सड़कों, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि, पेयजल योजना व सिंचाई योजनाओं को जो नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ है इसके बारे में सकारात्मक चर्चा यहां पर पिछले काफी दिनों से चल रही है। जिसमें दोनों, पक्ष व विपक्ष, की तरफ से महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये और

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

02-09-2024/1515/ए.एस.-एन.जी/1

लोक निर्माण मंत्री.....जारी

सुझावों के साथ-साथ किस तरीके से हमें अपने प्रदेश को आने वाले समय में आगे बढ़ाना है, इस दृष्टि से भी सभी ने अपने मत को यहां पर रखा है। हिमाचल प्रदेश पूरे रूप से हिमालयन रीजन में आता है और यहां का strata and new found Himalayas हैं, जिस तरीके से हमें बरसात के मौसम में नुकसान देखने को मिल रहा है, उस पर इस माननीय सदन को गम्भीरता से मंथन, विचार और चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं यहीं पर ही नहीं रुकना चाहूंगा कि हमें इस पर चिंता ही नहीं व्यक्त करनी चाहिए बल्कि there should be an affirmative action on behalf of the State Government in liaison with the Centre Government. यह एक ऐसा विषय है जो प्रदेश के भविष्य व प्रदेश की आने वाली दिशा को तय करेगा। यह जो फिनोमिना हम देख रहे हैं, disaster prone areas में cloudburst के मामलों को प्रदेश में देख रहे हैं और ये सभी अब एक जगह तक सीमित नहीं हैं। आज प्रदेश के अलग-अलग कोनों में बरसातों का अत्याधिक कहर हो रहा है। खासकर प्रदेश के कोने-कोने के specific areas में cloudburst हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी सड़कों, बगिचों, निजी भवनों व घरों को भारी नुकसान हो रहा है और यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहूंगा कि हमें आने वाले समय में इसमें हर तरीके से because this issue is not only concerned or limited to the State of Himachal Pradesh, it is rather a national and a global phenomena. इसके ऊपर हर स्तर पर चर्चा हो रही है लेकिन हमें अपने प्रदेश के अंदर भी इन विषयों पर सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए और इन मामलों के जानकारों से expert advice भी लेनी चाहिए कि हमें प्रदेश में किस तरीके से construction activities को यहां की

geological परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए अमेंड करने की आवश्यकता है। हमें इस दृष्टि से भी काम करने की आवश्यकता है।

02-09-2024/1515/ए.एस.-एन.जी/2

अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर हमारे सभी साथियों ने अपने-अपने सकारात्मक विचार रखे हैं। जब यहां पर चर्चा हो रही थी तो विपक्ष के हमारे एक साथी कह रहे थे कि आपने (लोक निर्माण विभाग) व प्रदेश सरकार ने अपनी पिछली कमियों को मद्देनज़र रखते हुए इस बार क्या कार्य किए हैं। हमारे विपक्ष के साथी अभी इस माननीय सदन में नहीं हैं और मैं कहना चाहता हूं कि I want to assure the Hon'ble House that the Government and the Public Works Department in particular has learned from the shortcomings of the previous disaster that happened in the State last year i.e. in 2023 and after that affirmative action or rather I would say that preventive measures were taken by the Department ताकि इस समय हम आपदा को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं लेकिन resource mobilization, सड़कों पर समय से मशीनरीज़ पहुंचे, सड़कों को समय से बहाल किया जाए, उसके लिए हमने विभाग की ओर से affirmative action लिए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मानसून के दौरान दिनांक 31-07-2024 से हुई भारी बरसात व बादल फटने के कारण प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की सड़कों को बहुत बूरी तरह क्षति पहुंची है और यात्रियों को असुविधा न हो उसके लिए यातायात को दूसरे लिंक रोड के माध्यम से भेजना शुरू किया गया। मानसून आपदा के चलते प्रदेश में सड़कों तथा पुलों का व्यापक नुकसान हमें इस बार भी पहुंचा है। हमारी सरकार द्वारा बिना समय गंवाए राहत और पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया गया तथा बहुत ही कम समय में मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक को खोलने का प्रयास किया गया। पिछली बार की आपदा से शिक्षा लेते हुए हमने इस

वित्तीय वर्ष में लगभग 20 करोड़ रुपये के वैली ब्रिजिज़ प्रिक्योर किए in anticipation of what forthcoming disaster would be in the State और

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

02.09.2024/1520/केएस/डीसी/1

लोक निर्माण मंत्री जारी----

उस दृष्टि से हमने 20 करोड़ रुपये के ब्रिजिज़ परचेज़ किए और इस आपदा के दौरान लोक निर्माण विभाग की सड़कों के 7 पुल भी क्षतिग्रस्त हो गए थे जिनमें से तीन पुल क्षतिग्रस्त हुए और चार पुल बह गए जिससे यातायात बंद हो गया। इस छोटी सी अवधि में विभाग ने जिला कुल्लू के तीन बेली ब्रिजिज़, 100 फुट का डीडी बागी पुल में, 180 फुट का डीडीआर केदस पुल में और 120 फुट का डीडीआर बॉयल पुल का कार्य पूर्ण किया और वाहनों की आवाजाही के लिए उसको रिकॉर्ड 15 दिन के कार्यकाल में खोला गया। जबकि एक-डेढ़ या दो महीने का समय लगता था, इसको रिकॉर्ड 15 दिन के अंदर लोक निर्माण विभाग ने शुरू करवाया है। इन तीन पुलों का निर्माण कार्य रिकॉर्ड 14-15 दिन के अंदर पूर्ण किया गया। सभी पुलों का निर्माण कार्य दिनांक 18.08.2024 तक सम्पन्न किया गया। इस आपदा के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को पुनः यातायात योग्य बनाने के लिए विशेष अभियान कार्य किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त मैंने पीछे भी मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद किया, हमने प्रदेश के अंदर लगभग 30 करोड़ रुपये की नई मशीनरी- जे.सी.बी., पोक लेन मशीन और टिप्पर आदि प्रदेश के अंदर प्रक्योर किए और प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के अंदर उनको डिप्लॉय किया। जब भी इस तरीके की प्राकृतिक आपदा किसी भी क्षेत्र में खासकर जो हमारे दूर-दराज के इलाके हैं, जनजातीय इलाके हैं, उनमें आए तो वहां के लिए हमने उनको ऑन प्रायोरिटी डिप्लॉय किया और डिजास्टर के समय में इन इलाकों में इसका सही इस्तेमाल हुआ है। यह हमारी खुशकिस्मती भी है कि इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश का पिछले साल की तुलना में कम नुकसान हुआ है मगर फिर भी हमने युद्धस्तर पर इस तरीके के कार्य प्रदेश

के कोने-कोने में करवाए और अभी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत 37 करोड़ रुपये लोक निर्माण विभाग को मिले हैं जो हर डिविज़न के लिए हमने दो दिन पहले बराबर एलोकेशन की है ताकि आर.एण्ड आर. में हमारे प्रदेश के अलग-अलग डिविजन्ज़ के अंदर जितना भी नुकसान हुआ है, उसकी हम भरपाई कर सके। We have taken this issue seriously with the Central Government. अभी मैंने प्रश्नकाल के दौरान भी इस बात का ज़िक्र किया है कि जितना हमारा the cumulative loss of Public Works Department in the entire State were of Rs. 45 thousand crores last year and this time it has exceeded around Rs. 500 crores. We have made the entire report which has

02.09.2024/1520/केएस/डीसी/2

been submitted to the Ministry of Road Surface and Transport, Government of India. हमने सी.आर.एफ. के माध्यम से और सैंट्रेल स्पेशल असिस्टेंस से हर तरीके से प्रदेश को सहयोग मांगने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में कोई राजनीति नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने हमेशा यही बात कही है कि जब प्रदेश में इस तरीके की कोई प्राकृतिक आपदा आती है, then we have to rise above the party politics. But I am sorry to say that the Hon'ble Leader of Opposition Shri Jai Ram Thakur Ji does not understand the 'b' of bipartisan politics. He doesn't understand it means to rise above the party lines and to raise the issues of the State with the Central Government collectively. Last year Hon'ble Chief Minister has called a Special Assembly of Vidhan Sabha where a Resolution was passed to get support of around Rs. 12500 crores from the Central Government मगर आज तक नेता प्रतिपक्ष ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी साथी ने इसके बारे में न चिंता व्यक्त की है, न इसके बारे में कोई बात की है। Capital infrastructure, making of roads और जो हमारा एग्जिस्टिंग नेटवर्क हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 41,186 किलोमीटर का है, इसकी अपग्रेडेशन, इसकी मेंटिनेंस समय-समय पर करना और particularly in areas that have been affected by the rainfall or heavy disaster उसको करने के लिए हमें जिस तरीके से केंद्र सरकार से रिसार्सिज़ मिलने चाहिए, अध्यक्ष महोदय वह नहीं मिल रहे हैं लेकिन मैं आपको इस विषय में भी बताना चाहता हूं कि

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

02.09.2024/1525/av/dc/1

लोक निर्माण मंत्री--------जारी

हमने आने वाले समय में चाहे वह हमारे राज्य मार्ग हैं, नेशनल हाईवेज हैं या फोर लेन के प्रदेश के अंदर काम चले हुए हैं; उनकी प्रदेश के अंदर रीअलाइनमेंट की जरूरत है। पिछली आपदा में हुए नुकसान के उपरांत हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नीतिन गडकरी जी ने खासतौर से कुल्लू-मनाली और मण्डी का दौरा किया था। उसमें उन्होंने यह चिंता जाहिर की थी कि जिस तरीके से हमारे इन इलाकों में फोर लेन की वर्टिकल यानी 90 डिग्री पर कटिंग करवाई गई तथा रिटेनिंग वॉल्ज और सब-स्टेंडर्ड डंगे लगाए गए हैं, उसके कारण हमारे कुल्लू-मनाली से लेकर ब्यास नदी के बेसिन पर जितने इलाके आते हैं वहां लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा है। मण्डी में पण्डोह ब्रिज बह गया था। ब्यास नदी के ऊपर हमारी जल शक्ति विभाग की स्कीम्ज और एस0टी0पीज0 इत्यादि सारे-के-सारे क्षतिग्रस्त हुए हैं जिससे जल शक्ति विभाग को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचा। हमारी ब्यास नदी के ऊपर जो मिटिगेशन होनी है उसकी लगभग अढ़ाई हजार करोड़ रुपये की डिटेल्ड रिपोर्ट सेंट्रल वॉटर कमीशन और केंद्र सरकार को भेजी है जिसका जिक्र माननीय उप-मुख्य मंत्री जी ने किया है। इसके अतिरिक्त हमारी सुकेती खड्ड जो मण्डी से सुन्दरनगर की ओर आती है, उसमें भी बहुत नुकसान हुआ है। अभी जिसका जिक्र माननीय सदस्य श्री चंद्र शेखर जी ने किया है। हमारा जो ब्यास नदी का हमीरपुर तक रिवर बेसिन है उसमें जिस तरह से हमारे जल शक्ति विभाग की स्कीम्ज को नुकसान पहुंचा है, वह बड़ी चिंता का विषय है। इसमें आने वाले समय में मिटिगेशन और चैनेलाइजेशन के माध्यम से इसमें रिस्टोरेशन की आवश्यकता है। But I want to highlight जिस तरीके से खासकर वहां फोर लेन की कटिंग हुई है इसमें माननीय श्री नीतिन गडकरी साहब ने भी कहा है कि इसकी रीअलाइनमेंट करने की आवश्यकता है। Preferably in the times to come टनलिंग की ओर जिसमें कम-से-कम कटिंग हो उस दृष्टि से काम करने की आवश्यकता है। अभी हाल ही में हम दिल्ली गए थे तो मैंने और मुख्य रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे 2

महत्वपूर्ण टनल्स के संदर्भ में मामले को माननीय श्री नीतिन गडकरी साहब से उठाया था। हमारी भू-भूजोत टनल स्ट्रैटेजिक प्वाइंट ऑफ व्यू, डिफैंस प्वाइंट ऑफ व्यू और टूरिज्म प्वाइंट ऑफ व्यू से और छोटा भंगाल, जोगिन्द्रनगर और एंटायर कुल्लू-मनाली की इकॉनोमी इम्प्रूव करने के लिए मैं

02.09.2024/1425/av/dc/2

समझता हूं कि यह मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस टनल के निर्माण के लिए हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि पठानकोट-मण्डी स्ट्रैच से जोगिन्द्रनगर में भू-भूजोत टनल का निर्माण कुल्लू की लग वैली क्षेत्र के लिए करवाया जाए। हमारी इसमें प्राथमिकता रहेगी और आने वाले समय में जब यह टनल बनकर तैयार होगी। इसमें हमारा जिस तरीके से खासकर पण्डोह के अंदर नुकसान हो रहा है क्योंकि पण्डोह में पीछे लगभग 60 करोड़ रुपये की रिटेनिंग वॉल लगी है जिसका टैंडर एन0एच0ए0आई0 द्वारा लगाया गया था।। believe it is absolute waste of public exchequers money जिस तरीके से ये रिटेनिंग वॉल्ज जगह-जगह पर लगाई जा रही हैं। इसलिए आने वाले समय में हमें इन चीजों पर जाने की आवश्यकता है। हम जितनी मैक्सिमम टनल्स बनाएंगे, उनकी अलाइनमेंट सही होंगी तो आने वाले समय में ये डिजास्टर कम हो सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूं। इसी तरीके से दूसरा नेशनल हाईवे 305 में ऑट से लेकर लूहरी तक भी हमने प्रपोज किया है कि हम जलोड़ी जोत के अंदर टनल का निर्माण करवाना चाहते हैं जिसके लिए 20 करोड़ रुपये का पी0एम0सी0 कॉंट्रैक्ट लोक निर्माण विभाग के नेशनल हाईवे डीविजन के द्वारा करवाया गया है।

टी सी द्वारा जारी

02.09.2024/1530/टी0सी0वी0/एच0के0-1
माननीय लोक निर्माण मंत्री .... जारी

यह भी टूरिज्म प्वाइंट ऑफ व्यू से और unnecessary cutting of trees हो रही है expansion of roads की वजह से जो समस्याएं आ रही हैं, उसको मिटीगेट करने के लिए, tourism point of view से यह दोनों टनल्ज कुल्लू और मनाली रीजन में महत्वपूर्ण साबित होंगी। इनके लिए भी हम प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, चम्बा-चवाड़ी का भी सरकार निश्चित तौर पर ख्याल रखेगी और इसको भी प्राथमिकता के आधार पर केन्द्र सरकार के समक्ष रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज मैं जो बातें कर रहा हूं ये मैं इनको public works के perspective से नहीं कह रहा हूं, it is not only for the creation of road network in the state but it is for having the alternative and a most sustainable network in the state, जिससे कम-से-कम डेमेज एनवायरनमेंट को हों। हमें प्रदेश के अंदर विकास को ही नहीं देखना है बल्कि प्रदेश के अंदर सस्टेनेबल डवलपमेंट हो, उस दृष्टि से कार्य करने की आवश्यकता है। Because we owe this. I sincerely believe कि सरकारें आएंगी, सरकारें चली जाएंगी। We owe this to the future generation of Himachal Pradesh. जो भी डवलपमेंट हिमाचल प्रदेश के अदंर हो वह सस्टेनेबल हों, वह हिमाचल प्रदेश इकोलॉजी, फ्लोरा, फोना और हिमाचल प्रदेश के एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए हों, यह हमारी सोच है। इसको खासकर लोक निर्माण विभाग के अंदर पूरी मजबूती से लागू करने का प्रयास करेंगे। मैं ज्यादा लम्बा समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि सभी माननीय सदस्यों ने इस विषय पर बड़े विस्तार से सकारात्मक विचार दिए हैं। विशेषकर जो नये माननीय विधायक अभी चुनकर आए हैं उन्होंने बहुत ही सकारात्मक विचार यहां पर दिए हैं। माननीय विधायक सुश्री अनुराधा राणा जी ने भी अपने बहुत ही सकारात्मक विचार इन विषयों पर दिए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम उन सबको inculcate करेंगे और इससे प्रदेश का विकास होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रदेश के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, सड़कों का निर्माण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। **But I want to assure the Hon'ble House that the development will be done in a sustainable manner, it will be done in a responsible manner and it will not be done at the cost of environmental degradation in the State of Himachal Pradesh.** अध्यक्ष महोदय, यह मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को बताना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मौसम विभाग के सर्वे के अनुसार अभी 10-15 दिन

तक मानसून प्रदेश के अंदर रहेगा उसके लिए भी the department of PWD is on tenterhooks. जहां पर भी सड़कें बंद होनी की समस्या आएगी या अपर में वैली ब्रिज लगाने की बात है हम पर्टिकुलरली उसके ऊपर एक्शन लेंगे। And I want to thank the Hon'ble Chief Minister that in this financial year also we have been sanctioned additional 20 crores rupees for procurement of bailey bridges. इसकी प्रक्योरमेंट शुरू कर दी गई है। Which will be placed in various parts of Himachal Pradesh, particularly in the hilly areas and in the tribal areas and **in the disaster prone area wherever we have to have any kind of mitigation work it will be done on priority and the people of that area will not face any inconvenience, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।**

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका एक बार पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द, जय हिमाचल।

02.09.2024/1530/टी0सी0वी0/एच0के0-3

अध्यक्ष : अब चर्चा में श्री संजय रत्न जी भाग लेंगे।

श्री संजय रत्न (ज्वालाजी) : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में भारी बरसात/आपदा के कारण जनमानस, सड़कों, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि, पेयजल व सिंचाई योजनाओं को पिछले साल और इस साल जो नुकसान हुआ है, मैं उसके ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश में आपदा आई जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश में दो प्रकार से आपदा आ रही है। एक तो प्राकृतिक आपदा है और दूसरी मैनमेड है।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

2-09-2024/1535/एन0एस0-एच0के0/1

श्री संजय रत्न----- जारी

मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने दोनों ही आपदाओं से प्रदेश को भी उभारा है और कांग्रेस पार्टी की सरकार को उभार कर जनता की सेवा के लिए रखा है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरी कोशिश की गई कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार टूट जाए। हमारे लोगों को प्रलोभन दिए गए। विपक्ष का तिहरा चेहरा है। एक व्यक्ति होता है जिसके दोहरे चेहरे होते हैं लेकिन इनके तीन चेहरे हैं। सदन के अंदर कुछ और बाहर कुछ बोलते हैं लेकिन जब दिल्ली में अपने आकाओं के पास जाते हैं तो कुछ बोलते हैं। पिछले वर्ष प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी आई और यहां पर ये (विपक्ष) स्पैशल सेशन बुलाने की बात करते रहे कि विधान सभा का सत्र बुलाओ। जब मुख्य मंत्री जी ने विधान सभा का सत्र बुलाया और तीन दिन तक चर्चा चली। तीन दिन चर्चा इसलिए चली कि पक्ष व विपक्ष के लोग इकट्ठा होकर काम करें कि इस त्रासदी से ऊपर कैसे निकला जाए और केंद्र सरकार को एक रेजोल्यूशन पास करके भेजें कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का मतलब यह था कि जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ उसमें हमें केंद्र सरकार से सहायता मिले। लेकिन हमारे मित्रों ने जब तीन बाद रेजोल्यूशन पास करने का समय आया तो वे वाकआउट करके यहां से चले गए। वे प्रदेश हित में बात नहीं करना चाहते थे। वे लोगों के बारे में चिंतित नहीं थे। वे केवलमात्र विपक्ष की भूमिका निभाने यानी विरोध करने में व्यस्त रहे। पिछले वर्ष आपदा के कारण हिमाचल प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो हिमाचल प्रदेश में 9905.77 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष रूप से नुकसान हुआ है। अगर इस आंकड़े को अप्रत्यक्ष रूप में शामिल कर लें तो 12,000 करोड़ रुपये का नुकसान पिछले वर्ष हुआ। पिछले वर्ष 500 से अधिक लोगों की जानें गईं लेकिन इस आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय, यहां तक कि जो हमारी पंच वर्षीय योजनाएं हैं, 15वें वित्तायोग जिसमें हमें वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2025-26 तक 50 करोड़ रुपये सालाना यानी 250 करोड़ रुपये मिलना था, अभी तक केंद्र सरकार से उसमें से भी कोई भी पैसा नहीं मिला है। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के नुकसान को देखते हुए रिलीफ मैन्युअल में बदलाव किया और बदलाव

2-09-2024/1535/एन0एस0-एच0के0/2

करने के उपरांत लोगों को राहत पहुंचाई। पहले पशु मरने पर 37,500 रुपये मिलते थे उसको 55,000 रुपये किया। 146 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। बकरी, सुअर, भेड़ और अन्य पशुओं के मरने पर 4,000 रुपये मिलते थे, उसको 6000 रुपये किया गया। दुकान, ढाबे आदि के नुकसान पर कुछ नहीं मिलता था उसमें भी 1 लाख रुपये देने का प्रावधान किया। वस्त्र, बर्तन, घरेलू उपयोग की चीजें जिन पर 25,00 रुपये मिलते थे उसको भी 50,000 रुपये किया। दो हजार प्रतिशत बढ़ोतरी की। फसल के नुकसान के ऊपर 680 रुपये प्रति बीघा मिलते थे उसको 4,000 रुपये प्रति बीघा किया और इसमें 588 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। कृषि एवं बागवानी भूमि से गाद निकालने के लिए 1440 रुपये प्रति बीघा मिलता था जिसको 5,000 रुपये किया गया जिसमें 694.47 प्रतिशत की वृद्धि की गई। कृषि एवं बागवानी भूमि की क्षति पर 3760 रुपये प्रति बीघा मिलता था जिसको 10,000 रुपये प्रति बीघा किया गया और इसमें 265 प्रतिशत की वृद्धि की गई। इस तरीके से मुख्य मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया। मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश के लोग उसी तरीके से जीवन निर्वाह कर रहे हैं जिस तरीके से वे डिजास्टर से पहले रहते थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार भी बहुत नुकसान हुआ और पिछले वर्ष भी बहुत नुकसान हुआ।

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

02.09.2024/1540/RKS/YK-1

श्री संजय रत्न ....जारी

आपने पिछली बार विधायक विकास निधि से डंगे लगाने के लिए ऑथोराइज किया था। इन डंगे लगाने का कार्य 31 मार्च तक अलाउ था। मेरा आग्रह है कि इन डंगे लगाने का कार्य कंटिन्यू किया जाए क्योंकि अभी भी बरसात के कारण बहुत से घरों के डंगे टूट रहे हैं या फिर पिछेल कुछ डंगे अभी तक नहीं लगे है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा

कि इस कार्य को जारी रखा जाए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब डिजास्टर आता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इस आपदा से कैसे उभरा जाए। डिजास्टर आने से पहले क्या प्रीकॉशन लेनी चाहिए उसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जब डिजास्टर आता है तो लोगों की सहायता के लिए सरकार कार्य करती है। अगर हम डिजास्टर आने से पहले गर्मियों में ही उससे बचने के उपाय सोच कर रखें तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं। केंद्र सरकार से हमें डिजास्टर के लिए पैसा मिलता है लेकिन मेरा आग्रह है कि केंद्र सरकार को भी डिजास्टर से बचने के एक दूरगामी योजना बनानी चाहिए। केंद्र सरकार को पहाड़ी राज्यों के लिए एक अलग सी योजना बनानी चाहिए। प्रदेश सरकारों को भी इसमें केंद्र सरकार की सहायता करनी चाहिए। अगर हम ऐसी योजना बनाएं तो केंद्र सरकार द्वारा जो डिजास्टर में बाद में पैसा जारी किया जाता है उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। हमें इसके लिए पहले ही प्रीकॉशनरी मेजरमेंट ले लेने चाहिए। अगर हम पहले ही प्रीकॉशनरी मेजरमेंट ले लें तो हमारा नुकसान भी कम हो सकता है। यह ठीक है कि नुकसान नेचर के हाथ में हैं और नेचर के साथ कोई नहीं लड़ सकता। हम कोशिश कर सकते हैं और कोशिश करके ही हम इस चीज से अपने आपको उबार सकते हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी पिछली बार बहुत नुकसान हुआ था। वहां बहुत सी सड़कें व पीने-के-पानी की स्कीमें पानी में बह गई थी। बिजली की व्यवस्था खराब हो गई थी। मेरे चुनाव क्षेत्र में जंदराह से सीहोरवाला सड़क सी.आर.एफ.के तहत बनी थी। इस सड़क के निर्माण कार्य में लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। हमने उस सड़क को टेंपरेरी तो रिस्टोर कर दिया है लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री और पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसमें मिटिगेशन करके पैसा जारी करें। उस सड़क की लगभग 18 करोड रुपए की डी.पी.आर.बनी है। मेरे चुनाव क्षेत्र में मिटिगेशन्ज की दो और स्कीमें एक ज्वालामुखी शहर में खारा नाला को चैनलाइज

02.09.2024/1540/RKS/YK-2

करने और दूसरी व्यास नदी से जो लूथान, कौ-सेंचुरी को नुकसान हुआ था, की भी मिटिगेशन के जरीए डी.पी.आर. अप्रूवल होने के लिए गई है। अगर आप इन तीनों स्कीमों

के लिए फंड प्रोवाइड कर दें तो हमारे क्षेत्र में जो दिक्कत आ रही है, हम उस दिक्कत से उबर सकते हैं। पिछली बार जो डिजास्टर आया था उसमें मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पांच गांव की जमीनें धंस गई थीं। लोगों के घर उजड़ गए, जमीनें बैठ गई और काफी घरों में दरारें आ गई थी। उस जमीन में दोबारा घर बन सकता है या नहीं उसका हमने उस वक्त सर्वे करवाया था। सेंटर्ल यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर की टीम सर्वे करने के लिए वहां आई थी लेकिन उसकी रिपोर्ट क्या आई उसका कोई पता नहीं है। हम अभी तक लोगों को जमीन नहीं दे पाए क्योंकि वह जंगल का एरिया है, डी.सी. अलॉटमेंट की लैंड नहीं है इसलिए हमें जमीन देने में बहुत दिक्कत आ रही है। वे लोग अभी भी लोगों के घरों में रह रहे हैं या एकाध कमरा किराये पर लेकर रह रहे हैं। कुछ लोग अपना एक छोटा सा कमरा बनाकर उसी जमीन के आसपास रह रहे हैं। वे परिवार के मुताबिक अपना बहुत बड़ा आशियाना नहीं बना पा रहे हैं। अगर हम इस जमीन के बारे में एक सर्वे करवाकर उन लोगों को यह बता दें कि यह जमीन रहने लायक है या नहीं तो वे लोग उस हिसाब से मकान बना सकते हैं। अगर वह जमीन रहने लायक नहीं है तो हमें उनको दूसरी जगह जमीन अलॉट करने के लिए प्रोसैस जारी करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो वे लोग कहीं से भी उधार लेकर अपनी जमीन परचेज कर सकते हैं। लेकिन लोगों को अभी भी यह लगता है कि शायद यह जमीन सेटल हो जाए और हम वहां दोबारा से अपना मकान बना सकें। अगर वे उस जमीन पर सर्वे की रिपोर्ट के बिना ही दोबारा से मकान बना लें और बरसात में वहां फिर से नुकसान हो जाए तो इन चीजों से बचने के लिए हमें पहले ही उस जमीन के स्ट्राटा को देख लेना चाहिए। मेरा राजस्व मंत्री जी से आग्रह है कि जो टीम आई थी उस टीम से उस जमीन को असैस करवा लिया जाए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पांच गांव इस खतरे की चपेट में हैं। पुखरू पंचायत में चौकी गांव, दोररू, लोअर अम्बाड़ा और मंझीड़ एरिया में भटाल खुरद के गावं इस डिजास्टर में धंस गए थे। हमने इन गांवों को खाली करवा कर लोगों की सरकारी भवनों में रहने की व्यवस्था की थी। हमने लोगों को रहने के लिए किराया भी दिया है।

श्री बी.एस.द्वारा....जारी

श्री संजय रत्न जारी...

ऐसे मेरे पांच गांव हैं जो बिल्कुल धंस गए थे और बिल्कुल बैठ गए थे। इन गांवों को हमने खाली करवा कर लोगों को सरकारी भवनों में रखा था। जब मुख्य मंत्री महोदय ने उन्हें किराया देने की बात की थी तो उन्हें किराया भी दिया गया था। लेकिन अब एक साल बीत गया है और एक साल के बाद भी हम यह निर्णय नहीं ले पाएं हैं कि ये लोग कहां जाएं। वर्ष 2013 में मेरे चुनाव क्षेत्र में त्रासदी आई थी और लंगड़ू पंचायत के तली गांव में हमारे 20-25 घर गुज्जर समुदाय के घर धंस गए थे। उस वक्त मुख्य मंत्री माननीय वीरभद्र सिंह जी थे और हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस वक्त भी हमें यह दिक्कत आई थी कि यह जंगल की जमीन है और हम इसे कैसे दे सकते हैं? उस वक्त भी कैबिनेट में जा करके और वन विभाग से बात करके उन लोगों को एक जमीन का टुकड़ा आबंटित किया गया और उन 15 घरों को वहां पर फिर बसाया गया था। आज वे लोग वहां पर बसे हुए हैं। इसी तरीके से यदि हम इन पांच गांवों को किसी तरीके से कैबिनेट में जा करके किसी भी तरीके से नियमों को छूट दे करके जमीन मुहैया करवा दें तो इन लोगों को जो मुख्य मंत्री जी ने त्रासदी में सात लाख रुपये देने की बात की है, उसकी इन्हें पहली किस्त तीन लाख रुपये की मिल चुकी है। लेकिन ये लोग घर नहीं बना पा रहे हैं। मेरा राजस्व मंत्री जी से निवेदन है कि इसके ऊपर जल्द-से-जल्द निर्णय होना चाहिए ताकि लोगों को घर बनाने में जो दिक्कत आ रही है वे जल्दी-से-जल्दी अपना आशियाना, घर बना कर वहां पर रहें। अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में और भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई मुख्य मंत्री और सरकार ने की थी लेकिन इस बार भगवान की दया से ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है और हमें उम्मीद है कि भगवान इस बार ऐसा नुकसान नहीं करेंगे। क्योंकि मुख्य मंत्री जी के स्टार बहुत अच्छे हैं पिछले साल भी त्रासदी में उभर कर आए थे और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा डिजास्टर था, मुख्य मंत्री जी उससे भी उभर कर आए हैं। मुझे नहीं लगता कि भगवान ऐसा कोई हमारे साथ अन्याय करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान का आशीर्वाद प्रदेश की जनता के साथ रहेगा और मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार इन चीजों से उभर कर प्रदेश की सेवा करेगी। जिसके लिए प्रदेश की जनता ने हमें चुन करके भेजा है। हम पांच साल तक जनता की सेवा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। यह जो दो-तीन बातें मैंने की हैं, राजस्व मंत्री जी, इनके ऊपर जल्द-से-जल्द

गौर किया जाए ताकि ये लोग अपने-अपने घर बना सकें और दोबारा से उसी जीवन को जी सकें। जिस तरीके से ये त्रासदी से पहले जी रहे थे, धन्यवाद।

02.09.2024/1545/बी.एस./वाई. के-2

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी चर्चा में भाग लेगे।

श्री सुरेश कुमार (भोरंज): अध्यक्ष महोदय, जो नियम-130 के अन्तर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लाई गई है। इस पर बोलने के लिए मैं भी अपने आप को शामिल कर रहा हूं। ये मुद्दा बड़ा गंभीर है और विपक्ष की तरफ से यह आया है लेकिन हमें बड़ी निराशा हो रही है और बड़ा दुःख हो रहा है कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा इस माननीय सदन में रखा गया और आज विपक्ष नदारद है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा जो विपक्ष है वह प्रदेश की जनता के प्रति कितना संवेदनशील है और इस सदन में जो महत्वपूर्ण चर्चा लाए हैं उसके बाद भी स्वयं गायब है, यह बड़ा निंदनीय विषय है। अध्यक्ष महोदय, पिछली वर्ष इस प्रदेश के अन्दर एक बड़ी त्रसदी आई और उस त्रसदी ने प्रदेश के कई परिवारों को उजाड़ दिया और कई जानें चली गईं, पशुधन का नुकसान हुआ और जमीने बह गईं और प्रदेश संकट में घिर गया। लेकिन जितनी सूझबूझ के साथ जितनी होशियारी के साथ हमारी सरकार और मुख्य मंत्री जी ने इस त्रासदी को संभाला यह बहुत प्रशंसनीय कार्य है। इस कार्य की प्रशंसा न केवल विभिन्न संस्थाओं ने कीं परंतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर ने भी प्रशंसा की जिसमें नीति आयोग था, हमारा वर्ल्ड बैंक था और यहां तक की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय शांता कुमार जी ने भी मुख्य मंत्री जी की पीठ थपथपाई और उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री जी ने त्रासदी से इस प्रदेश को बड़ी सूझबूझ के साथ और बड़ी हिम्मत के साथ उबारा है। इस त्रासदी पर जब दूसरी बार चर्चा आई तो

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

02.09.2024/1550/डी0टी0/ए0जी0-1

श्री सुरेश कुमार जारी...

हमें ये मालूम हुआ कि पिछले वर्ष जब प्रस्ताव लाया गया था उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे विपक्ष के साथियों ने इसका बहिष्कार किया था और इस वक्त भी वह इस चर्चा से नदारद हैं। इससे इनके इस चरित्र का पता लगाया जा सकता है कि वे न तो पहले गम्भीर थे और न वो अब गम्भीर हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में पिछले वर्ष जो त्रासदी आई उसमें प्रदेश को लगभग 9300 करोड़ का नुकसान हुआ। केंद्र सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजी गई। आज पूरा एक वर्ष हो गया है लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अभी तक कोई सहायता इस प्रदेश को नहीं मिल पाई है। अपने सुक्षम साधनों के बावजूद माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश को 4500 करोड़ रुपये का एक आर्थिक पैकेज दिया जिस की वजह से प्रदेश के लाखों परिवारों को संकट से उभारने का काम हमारी सरकार ने किया। मैं पूरे प्रदेश के साथ-साथ अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान भारी बाढ़ के कारण हुआ। माननीय मुख्य मत्री जी व्यक्तिगत रूप से वहां पर गये, वहां जाकर सारे नुकसान का ज़ायजा लिया और लोगों के दुख-दर्द को बांटा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुल 8 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। 190 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे। इन 8 परिवारों को 7-7 लाख रुपये के हिसाब से इस समय तक 46 लाख 58 हज़ार रुपये की राशि अदा कर दी गई है। उनको 9 लाख 50 हज़ार रुपया देना अभी बाकि है। क्योंकि उनमें से एक परिवार का घर वन भूमि में था और जब वह घर गिरा उसके बाद वन विभाग ने दोबारा वहां पर घर बनाने की अनुमति नहीं दी। वह पैसा अभी भी वैसे का वैसा ही पड़ा है। बाकि के जो 7 प्रभावित परिवार हैं उनको लगभग पैसा मिल चुका है इनमें से किसी का 20 हज़ार बचता है, किसी का 30 हज़ार बचता है। कहने का अर्थ है कि बहुत थोड़ी राशि ऐसे प्रभावित परिवारों को देना शेष है, जब कम्पलीशन का यू0सी0 आ जायेगा तो वह पैसा भी उनको दे दिया जायेगा। इसी के साथ जो 190 आंशिक रूप से प्रभावित परिवार थे उनको भी हमारी सरकार ने 1 करोड़ 90 लाख की राशि वितरित कर दी है और इन लोगों का जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर दी गई है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में कई ऐसे कार्य अभी रह गये हैं और बहुत सारे ऐसे मकान भी रह गयें हैं जिनकी असेसमेंट बाद में नहीं हो पाई, पटवारी वहां तक नहीं पहुंच पाये हैं, मेरा निवेदन रहेगा कि उन परिवारों को भी उनमें शामिल किया जाये और इस योजना का समय थोड़ा सा और बढ़ाया जाये ताकि पटवारी

02.09.2024/1550/डी0टी0/ए0जी0-2

गांव-गांव जाकर उन लोगों की रिपार्ट तैयार करें जो लोग इस सहायता से वंचित रह गये हैं ताकि उनको भी मुआवजा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार बड़ी खड्डें हैं जो मैदानी क्षेत्र में हैं और जब मैदानी क्षेत्र में पानी आता है तो वह ज्यादा तबाही मचाता है। मेरे विधान सभा में सीर, सुनैल, चैंथ और कुंणा खड्ड पड़ती है और इनमें जब पहाड़ों से उतर के पानी आता है तो ये खड्डें विकराल रूप धारण कर लेती है और जिससे लोगों के घरो और खेतों को नुकसान होता है। मेरा ये सरकार से अनुरोध भी है और ये सुझाव भी है कि कि इन खड्डों का अगर तटीकरण किया जाये तो लोगों के जान-माल की रक्षा की जा सकती है। इसके लिए विभाग ने मेरे विधान सभा क्षेत्र की दो खड्डों सुनैल व चैंथ खड्ड की डी0पी0आर0 भी तैयार की है। जहां तक सीर खड्ड की बात है मैंने इसका मुद्दा पहले भी उठाया था लेकिन सीर खड्ड के तटीकरण का मामला बहुत वर्षों से लंबित पड़ा है। उसका जो चैनलाइजेशन का कार्य है उसको भी किया जाना चाहिए। सीर खड्ड के लिए 157 करोड़ रुपये की डी0पी0आर0 पूर्व में बनी थी। उसका फाउडेशन स्टोन तात्कालिक मुख्य मंत्री माननीय प्रेम कुमार धूमल जी के द्वारा रखा गया था आज उस फाउण्डेशन स्टोन की ये हालत हो गई है उसके दोनों ओर पानी जमा हो चुका है। मैं ये कहना चाहता हूं इसके लिए पैसे का प्रावधान करवाया जाये और जो सीर खड्ड का चैनालाइजेशन है उसको किया जाये ताकि

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

02-09-2024/1555/ए.जी.-एन.जी/1

श्री सुरेश कुमार.....जारी

बड़ी आपदा से बचा जा सके। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के हमारे साथी यहां पर तरह-तरह के दोषारोपण करके गए हैं। मेरे क्षेत्र के साथ सरकाघाट विधान सभा क्षेत्र लगता है। वहां के

माननीय विधायक श्री दलीप ठाकुर जी नियम-130 के तहत चर्चा करते हुए कह रहे थे कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के सभी रोड बंद पड़े हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं कि जिन रोड्स की वे बात कर रहे हैं और उन्होंने जिस खास रोड पटड़ीघाट से चौक का जिक्र किया था, वह रोड बिलकुल चालू है और लोक सभा चुनावों के दौरान माननीय सांसद सुश्री कंगना रणावत के साथ श्री दलीप ठाकुर जी को उनकी गाड़ी में उसी रोड से जाते हुए मैंने स्वयं देखा था। मेरा कहना है कि विपक्ष के साथियों को झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए और अपने क्षेत्र की वास्तविक्ता को माननीय सदन में रखना चाहिए। इस प्रकार से विपक्ष के लोग झूठे आरोप लगाकर हमारी सरकार को कठघरे में खड़ा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपदा के समय में मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक अन्य मानव जनित आपदा भी हुई है। एन.एच.-70 मेरे विधान सभा क्षेत्र से होकर भी गुजरता है। उसको बनते-बनते चार साल हो गए हैं। वह वर्ष 2020 में बनना शुरू हुआ था और अभी तक वह बन नहीं पाया है। उसके निर्माण के दौरान अनेक पहाड़ियां काटी गई जिससे लोगों के घरों को काफी नुकसान हुआ है। पिछले वर्ष जब भारी बरसात हुई तो डंगों के गिरने के कारण लोगों के मकान, गौशालाएं आदि भी गिर गए। उस वक्त हमारे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन निर्माण कम्पनी और MoRTH की ओर से कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया। हमने व्यक्तिगत तौर से तिरपाल बांट कर लोगों की सहायता की और सरकार की ओर से भी सहायता दिलवाई।

(श्री संजय रत्न, माननीय सभापति पदासीन हुए।)

02-09-2024/1555/ए.जी.-एन.जी/2

सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि रोड बनने की वजह से जिन लोगों के घरों, रास्तों व गौशालाओं को नुकसान हुआ है, उनको उसका

मुआवजा संबंधित निर्माण कम्पनी के माध्यम से दिलावाया जाए। उस रोड का कार्य लम्बे समय से हो रहा है और निर्माण कार्य कब पूर्ण होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। मेरा आग्रह है कि इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए।

सभापति महोदय, यह प्राकृतिक आपदा की बात है और इस पर हम सभी को गहन चिंतन करने की आवश्यकता है तथा एक ठोस नीति के साथ हमें अपने लोगों की जान-माल की रक्षा करने की आवश्यकता है। हम इस माननीय सदन के अंदर महज बहस करें और उस दौरान एक-दूसरे पर दोषारोपण करें, गलतियां निकालें तो इससे आपदा का हल निकलने वाला नहीं है। जब भी कोई आपदा आती है तो वह बताकर नहीं आती। अभी ऐसा कोई भी यंत्र नहीं बना है जिससे आपदा का पता पहले ही चल जाए। लेकिन आपदा होने से पहले ऐसे उपाए जरूर कर लेने चाहिएं जिससे बाढ़, बादल फटने व अन्य आपदाओं से निपटा जा सके।

सभापित महोदय, इस माननीय सदन में प्राकृतिक आपदा के ऊपर सभी ने अपने-अपने विचार रखे और मैं भी इसके लिए कहना चाहता हूं कि यह आपदा भगवान की मर्जी से हुई है। इसके अलावा प्रदेश में एक आपदा विपक्ष के लोगों द्वारा भी खड़ी की गई है। इस प्रदेश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करके और खरीद-फरोख्त करके विपक्ष के लोग हमारी सरकार को अस्थिर करना व गिराना चाहते थे। विपक्ष के लोग इस प्रदेश के अंदर भय का माहौल पैदा करना चाहते थे। पिछले दिनों जब हमारी सरकार संकट से गुज़र रही थी तो उस वक्त नेता विपक्ष, श्री जय राम ठाकुर जी ने अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहा था कि "अब इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता"। मैं भगवान का और अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि हमारी सरकार को भगवान ने भी बचाया है और अध्यक्ष महोदय ने भी बचाया है। श्री जय राम ठाकुर जी ने अपने दोनों हाथ ऊपर करके जो कहा था वह न सुन कर भगवान जी ने हमारी बात को सुना और हमारी सरकार को बचाया।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

02.09.2024/1600/केएस/एएस/1

श्री सुरेश कुमार जारी---

और उसके बावजूद हमारी सरकार दोबारा से पूर्ण बहुमत के साथ आज इस सदन के अंदर बैठी हुई है। इसमें भगवान का भी साथ है और अध्यक्ष महोदय की सूझबूझ और उनका जो निर्णय था, उसका भी साथ है। ये लोग उस वक्त भी भटक रहे थे और आज भी भटक रहे हैं। इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इनको सुनने वाला कोई नहीं है। इनको न प्रदेश की जनता सुन रही है और न ही देश की जनता सुन रही है। इनको अपनी पार्टी भी नहीं सुन रही है इसलिए ये जगह-जगह भटक रहे हैं। इस हताशा के माहौल के अंदर कभी ये बॉयकॉट कर रहे हैं, कभी अध्यक्ष महोदय के बारे में अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, कभी मुख्य मंत्री जी के बारे में बाते कर रहे हैं। इनको पूरा प्रदेश देख रहा है और प्रदेश इनको कभी माफ नहीं करेगा। इस माननीय सदन में इतने गम्भीर मुद्दे आए हैं और उनसे विपक्ष नदारद है। नियम-130 का मुद्दा ये ले कर आए हैं, लॉ एण्ड ऑर्डर का मुद्दा ये ले कर आए हैं, लॉ एण्ड ऑर्डर के ऊपर भी बहस करने के लिए हमारी सरकार तैयार है लेकिन विपक्ष के लोग चर्चा से भाग रहे हैं। इन बातों का आपको संज्ञान लेना चाहिए और इस प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, सार्थक बात वह होती यदि हमारे विपक्ष के साथी इस चर्चा में गम्भीर होते और इनको प्रदेश की जनता की चिंता होती। पिछले दिनों जो इतनी बड़ी त्रासदी आई है, इनका यह कर्तव्य बनता था कि ये यहां पर उस सम्बन्ध में बहस भी करते और जो इस प्रदेश को नुकसान हुआ है, उसके लिए ये केंद्र सरकार के पास जाते और कहते कि प्रदेश की जनता को बहुत नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई करने के लिए आप हमें सहायता दो। अगर ये ऐसा कार्य करते तो देश और प्रदेश की जनता भी इनकी प्रशंसा करती लेकिन जिस तरीके से ये आज सदन को छोड़कर भाग रहे हैं और खुद चर्चा ला कर अनुपस्थित रह रहे हैं, इस तरह से इनकी गम्भीरता को पूरा प्रदेश देख रहा है।

सभापति महोदय, जो इस प्रदेश में त्रासदी आई है, इसके लिए हमें कई तरह के उपाय करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि बादल फटने की घटनाएं अब दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी क्योंकि जलवायु परिवर्तन के दौर से

02.09.2024/1600/केएस/एएस/2

गुज़र रहे हैं, अब बारिश कम हो रही है और बादल फटने की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। इसके लिए हमें तैयारी करने की आवश्यकता है और यहां ऐसे यंत्र लगाने की आवश्यकता है, ऐसी टैक्नीक लाने की आवश्यकता है जिससे हमें बादल फटने से पहले पता चल सके और लोगों को सचेत किया जा सके और उससे होने वाले नुकसान से बचा जा सके।

सभापति महोदय, हमारी बहुत सारी सड़कें गांव में ऐसी हैं कि जब बरसात होती है तो पानी निकलने के लिए उनमें नालियां नहीं बनी हैं। पानी एकदम से इकट्ठा होता है और जमीन को बहा कर ले जाता है जिससे लोगों को बहुत नुकसान होता है। हमें चाहिए कि गांव की सड़कों की नालियां भी ठीक बनें ताकि पानी का रास्ता न रुके।

सभापति महोदय, मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कहना चाहता हूं कि जो हमारी सड़कें हैं, उनमें जो टैलीफोन की तारें बिछाने के लिए खुदाई की जाती है तो बार-बार खुदाई करने से भी जमीन कच्ची हो जाती है और बरसात होने से उसमें पानी जमा हो जाता है, उसके बाद फिर वहां पर सड़क भी टूट जाती है और बहुत ज्यादा भूमि-कटाव हो जाता है। जो हमारे टैलीफोन विभाग के लोग हैं, कोई ऐसा तरीका बनाया जाए ताकि एक परमानेंट ट्रेंच हो। उसी में सारे विभाग तारें डाले। एक बार बी.एस.एन. वाले आते हैं, दूसरी बार एयरटैल वाले और तीसरी बार जिओ वाले आ कर उसी जगह को बार-बार खोदते हैं। इसलिए एक ऐसी टैक्नीक बनाई जाए कि एक ही बार खुदाई करें और उसी में सभी की तारें जाएं ताकि बार-बार सड़क को ना छेड़ा जाए। अगर हम इस तरीके के उपाय करेंगे तो हम आने वाली त्रासदी से बच सकेंगे।

सभापति महोदय, मैं माननीय सदन से कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से पिछले वर्ष हमने प्रस्ताव रखा था कि प्रदेश के अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हम केंद्र सरकार को लिखें, इस बार भी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए केंद्र को लिखा जाए और केंद्र से जो हमें सहायता मिलनी है, वह मिलनी चाहिए। वह हमारे प्रदेश के लोगों का हक है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

02.09.2024/1605/av/as/1

श्री सुरेश कुमार--------जारी

और वह हक़ हमारे प्रदेश को मिलना चाहिए। उसके लिए हमारे विपक्ष के साथियों को भी साथ चलना चाहिए क्योंकि यह प्रदेश हित का मुद्दा है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री अजय सोलंकी चर्चा में भाग लेंगे।

02.09.2024/1605/av/as/2

श्री अजय सोलंकी : अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल, श्री सुख राम चौधरी, श्री बलबीर सिंह वर्मा और श्री राकेश जम्वाल जी ने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा लाई है।

सभापति महोदय, आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पिछले वर्ष हमारे प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के कारण हर जगह हा-हाकार का माहौल बन गया था और थोड़ी जोर की बारिश शुरू होने पर दहशत का माहौल पैदा हो जाता था। आपदाएं तो पहले भी आती थीं परंतु पिछले वर्ष 8 जुलाई से लेकर सितम्बर माह तक जो आपदाएं आई उसमें प्रदेश के लोगों की प्राइवेट प्रोपर्टी और सरकारी संपत्ति का बहुत नुकसान हुआ था और जन-जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया था। हम आज उस पर चर्चा करने के लिए खड़े हुए हैं। यहां पर जिस तरीके से आपदा आई थी उसे देखकर ऐसे लगता था कि इससे निपटना मुश्किल है। लेकिन मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री, मंत्रीगण और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बधाई देता हूं कि जिस तरीके से इस आपदा के दौरान सरकार ने परफॉर्मेंस की है, उस आपदा से उभरने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने सबसे साहसिक कार्य जो किया है उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। इन्होंने रिलीफ मैनुअल चेंज किया और उस मैनुअल को वर्षों से कभी किसी ने हाथ नहीं

लगाया था। उस मैनुअल में चेंज करके लोगों को राहत पहुंचाई गई तथा उनके जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास किया गया। मैं मुख्य मंत्री जी और मंत्री गण को बधाई देता हूं। वैसे तो जब से यह सरकार बनी है माननीय मुख्य मंत्री जी हर आपदा से उभरकर और ज्यादा मजबूत बने हैं। सबसे पहले जब सरकार बनी तो आपदा के रूप में आर्थिक आपदा आई और प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था चरमरा चुकी थी। परंतु माननीय मुख्य मंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता से इन्होंने अपने सीमित संसाधनों के साथ जहां-जहां पर लीकेजिज थीं उनको बंद करके आपने जो राजस्व घाटे को कम किया है, मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहूंगा। इसके अतिरिक्त आपने जो अपनी सेविंग को प्रदेश हित में लगाया, आप उसके लिए और भी बधाई के पात्र हैं। पिछले वर्ष की आपदा के दौरान मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी भारी नुकसान हुआ था। वहां पर बहुत सारी पानी की स्कीम्ज, बिजली की लाइन्स ध्वस्त हो गई थीं। नाहन में वॉटर सप्लाई की स्कीम के आठ सब-स्टेशन्ज थे जोकि सभी जल मग्न हो गए। वहां पर बड़े-बड़े ट्रांसफॉर्मर्ज नष्ट हो गए। वहां बड़े-बड़े पहाड़ों के धंसने से सड़कों में बाधा आ रही थी। मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बधाई देता हूं कि सभी सड़कों को रिकॉर्ड टाइम में बहाल किया गया। **टी सी द्वारा जारी**

02.09.2024/1610/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

श्री अजय सोलंकी.... जारी

और उनकी परमानेंट रेस्टोरेशन का कार्य आज तक भी चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री और राजस्व मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी आपदाएं आईं हैं। मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र की आपदाएं अलग-अलग होती हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र के साथ पहाड़ी क्षेत्र भी पड़ता है। पिछले साल बरसात के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में लैंड स्लाइड हुए और मेरे क्षेत्र में 3-4 गांव बिल्कुल धंस गए। जैसा अभी माननीय सदस्य श्री संजय रत्न जी ने भी कहा कि जो गांव पूरी तरह से धंस गए थे, वहां से उन लोगों को टेंपरेरी बेस पर किसी अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया गया। उनके पास जमीनें तो हैं लेकिन वे उन पर मकान नहीं बना सकते हैं क्योंकि उन जमीनों पर वे कभी भी दोबारा आपदा शिकार हो सकते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए व मकान बनाने के लिए वन भूमि पर जगह दी जाए। आपदा के समय बहुत से लोगों के मकान ध्वस्त हो गए थे और वे रिलीफ पैकेज के बावजूद भी आज

तक अपने मकान नहीं बना पाए क्योंकि सरकार उन्हें मकान बनाने के लिए वन भूमि उपलब्ध नहीं करवा पाई। वे अभी तक भी सरकार द्वारा निर्धारित किराए के मकानों में रह रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस बारे में जल्द-से-जल्द निर्णय लें कि उन्हें कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए? मेरे विधान सभा क्षेत्र में मलगांव, शीलणू कैलाश और ग्राम पंचायत नाहन का कुछ क्षेत्र पूरी तरह से धंस गया है जहां लोग आज भी खतरे में जी रहे हैं। इसलिए इन क्षेत्र के लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए जमींन उपलब्ध करवाई जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र के मैदानी क्षेत्र में मारकण्डा नदी, सुंकर नदी, बाता नदी और जलमुसा नदी है जहां बरसात के दौरान भारी आपदा आती है। बरसात के दौरान मैदानी क्षेत्रों में इतना जल स्तर बढ़ जाता है कि बहुत-सी भूमि का भूमि कटाव हो जाता है और लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन सभी नदियों का तटीयकरण किया जाए। इनकी डी0पी0आर्ज0 विभाग ने सरकार को भेज दी हैं। उनको स्वीकृत किया जाए और इन नदियों की चेनलाइजेशन की जाए। जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो मैदानी क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ जाता है। जैसा यहां पर माननीय सदस्यों ने जिक्र किया कि पहले डंगों के लिए विधायक विकास निधि से पैसा दिया जाता था लेकिन मार्च के

02.09.2024/1610/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

पश्चात् नई गाइडलाइन्स आने के बाद इस निधि से डंगों के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि विधायक विकास निधि से इन ड़गों के लिए भी पैसा दिया जाए क्योंकि इस बरसात में भी बहुत नुकसान हुआ है। कई लोगों के मकान खतरे में हैं, कइयों की गऊशालाएं ध्वस्त हो गईं हैं। मेरा राजस्व मंत्री और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी से निवेदन है कि आपदा के दौरान ग्रांमीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा जो मकान स्वीकृति किए गए हैं उनको रिव्यू किया जाए क्योंकि उस समय जो सर्वे हुआ है, उसमें जागरुकता की कमी के कारण बहुत से लोग अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाए और पंचायत के लोगों ने भी शायद गम्भीरता से उनकी लिस्ट नहीं बनाई।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

2-09-2024/1615/एन0एस0-डी0सी0/1

श्री अजय सोलंकी----- जारी

मेरा निवेदन है कि उसमें इस वर्ष भी कुछ और सैंक्शन्ज दी जाएं ताकि जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको हम आपदा के माध्यम से मकान की स्कीम दे पाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो पिछला बजट पेश किया गया था उसमें विधायक निधि से हाउसिंग की स्कीम दे सकते हैं तो ऐसा जिक्र हुआ था। मेरा निवेदन है कि इसको जल्दी-से-जल्दी नोटिफाई किया जाए ताकि हम लोग उनकी सहायता कर सकें। मकान की स्कीम केवल अनुसूचित जाति और ओ0बी0सी0 वर्ग के लोगों के लिए ही मिलती है लेकिन बहुत से गरीब लोग अनुसूचित जाति और ओ0बी0सी0 वर्ग से बाहर की केटेगरी के हैं, उन्हें भी हम मकान की स्कीम दे पाएं ऐसा प्रावधान मुख्य मंत्री जी की दूरदर्शी सोच के साथ रखा गया है लेकिन इसे शीघ्रातिशीघ्र नोटिफाई किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी व राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। आपदा में जो स्पैशल रिलीफ दिया गया वह 8 जुलाई से 15 सितम्बर के मध्य दिया गया लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र के मैदानी क्षेत्र में 5 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें सर्दियों में भारी ओलावृष्टि हुई। ये पंचायतें मिस्रवाला, क्यारदा, माजरा, फतेहपुर और सैनवाला है। भारी ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल शत प्रतिशत ध्वस्त हो गई। वैसे तो प्रशासनिक अधिकारियों ने जिला स्तर पर सरकार को प्रपोज किया है। मेरा निवेदन है कि इस पर विचार करें क्योंकि शत प्रतिशत फसल इन 5 पंचायतों की क्षतिग्रस्त हो गई थी।

सभापति महोदय, विडम्बना यह है कि जो लोग इन मुद्दों को चर्चा के लिए लेकर आए वे आज इस माननीय सदन में मौजूद नहीं हैं और आज यहां से नदारद हैं। आज इस सत्र का पांचवां दिन है। पांचों दिन विपक्ष इस सदन में गंभीर नहीं दिखा। विपक्ष हर मुद्दे से भागता हुआ नजर आया।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय अपना बड़ा दिल करके विपक्ष को चर्चा के लिए समय देते हैं और मैं अभी प्रश्न काल के दौरान इस बात को देख रहा था। इसके बावजूद विपक्ष के माननीय सदस्य अपने चुनाव क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं हैं और सदन के प्रति भी गंभीर

नहीं हैं। केवल सनसनी फैला कर और मीडिया की सुर्खियां बटोरने के अलावा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने जब आपदाएं आईं तो उसमें भी अवसर ही तलाशे। आपदा में अवसर तलाशना कोई भाजपा के नेताओं से सीखें। हिमाचल प्रदेश में जब-जब आपदाएं आईं, पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदा आई और उससे पहले कोरोना के रूप में महामारी आई तो उस आपदा में भी अवसर तलाशे गए और इन अवसरों का इन्होंने भरपूर फायदा उठाया। अध्यक्ष महोदय, मैं मुद्दे से भटकाना नहीं चाहता लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना काल भी आपदा से कम नहीं था। जितना भ्रष्टाचार उस आपदा के दौरान पिछली भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ अगर उस पर चर्चा लाई जाए। आज जो विपक्ष यह चर्चा लेकर आया है अगर यहां बैठे होते तो मैं उनके समक्ष बोलना चाहता था। भारतीय जनता पार्टी सच्ची लोकप्रियता के अलावा सदन के प्रति गंभीर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। आपका बहुत धन्यवाद, जय हिंद।

अध्यक्ष -----आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

02.09.2024/1620/RKS/HK-1

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री सुदर्शन सिंह बबलू चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुदर्शन सिंह बबलू : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम-130 के तहत बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, हमारे भाजपा के एक सदस्य दो दिन पहले बोल रहे थे कि जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तब से प्रदेश में आपदा आनी शुरू हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि यह एक कुदरत का नियम है और आपदा किसी भी प्रदेश में कहीं भी और किसी भी समय आ सकती है। वर्ष 1988 में हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात हुई थी जिसके कारण निचले हिमाचल में भारी नुकसान हुआ था। जिला ऊना की चिंतपुरनी विधान सभा में उस समय बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। पिछले दो वर्षों में जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आपदा आई उसमें सैंकड़ों लोगों ने अपनी जान गवाई। यह एक बहुत ही दुःख का विषय है। इस बार भी बरसात ने पूरे हिमाचल के अंदर कहर भरपाया। हिमाचलवासियों ने इस आपदा में अपनी जानें गवाई है। श्री अजय सोलंकी जी ने कहा कि एक आपदा वर्ष 2020 में भी आई थी। कोरोना के रूप में जो आपदा आई थी उस समय

भाजपा की सरकार ने आपदा में जो अवसर ढूंढने की कोशिश की उनके बारे में श्री अजय सोलंकी जी ने बहुत अच्छे शब्दों में बताया है। मैं भी इस संदर्भ में अपने दो शब्द रखना चाहता हूं। उस समय की सरकार ने जो अपना कर्तव्य निभाया है वह जग जाहिर है। हिमाचल का बच्चा-बच्चा जानता है कि उन्होंने आपदा के अंदर कैसे अवसर ढूंढने की कोशिश की थी। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी और हर विषय के ऊपर राजनीति करना सही नहीं है। आज उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खूजी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश को संभाला है तब से आपदा आनी शुरू हुई है। यह बोलने की बात नहीं है लेकिन यह उनकी सोच दर्शाती है कि वे कांग्रेस या सरकार के प्रति किस तरीके का प्रशिक्षण लेकर आते हैं। वे ऐसा कहकर अपनी एक सस्ती लोकप्रियता हिमाचल के अंदर ढूंढना चाहते हैं। उन्होंने माननीय सदन के अंदर इस तरीके की बयानबाजी की है और मैं समझता हूं कि यह बहुत ही निंदनीय है। काफी सालों पहले भुज, उड़ीसा व उत्तराखंड में आपदा आई थी। मेरा कहने का मतलब है कि आपदा किसी भी सरकार के रहते आ सकती है। यह एक कुदरत की मार है। लेकिन ऐसी बयानबाजी करना बहुत ही निंदनीय है। मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ते हुए यह बोलना चाहूंगा कि जो 2 वर्ष पूर्व आपदा आई थी उस समय हम विधान सभा के अंदर उस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का संकल्प लेकर आए थे। लेकिन उस समय भाजपा के लोगों ने हिमाचल के हितों से मुंह फेर लिया और उस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित

करने में इन्होंने अपने सिग्नेचर तक नहीं किये। वे उस समय सदन से वाकआउट करके बाहर चले गए थे। मैं समझता हूं कि ये अपनी सस्ती लोकप्रियता तो ढूंढते हैं लेकिन जब हिमाचल के हितों की बारी आती है तो वे हिमाचल के हितों के लिए सरकार के साथ साथ खड़े नहीं होते। उन्होंने आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में जो अपना योगदान देना था, वह योगदान नहीं दिया और वे सभी लोग सदन से बाहर चले गए थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एक बड़ा दिल दिखा कर इस आपदा से निपटने के लिए 4500 करोड़ रुपये का बजट हिमाचलवासियों के लिए पेश किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपदा में लोगों के मकान गिरते थे तो पहले सरकार की तरफ से 1.30 लाख रुपये या डेढ़ लाख रुपये मुआवजे के रूप में मिलता था। पक्के मकानों के नष्ट

होने पर भी लोगों को इतनी ही राशि मिलती थी। लेकिन जिस तरीके से हिमाचल के अंदर नुकसान हुआ उस नुकसान को देखते हुए मुख्य मंत्री जी ने बड़ी सोच रखते हुए 4500 करोड रुपये का बजट पेश किया और उस कानून को बदल दिया जिस कानून के तहत हमें डेढ लाख रुपये मिलता था। हमारी सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दिया है और मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री और सभी सभी मंत्रियों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष एक और बात रखना चाहूंगा कि जो 7 लाख रुपये लोगों को मिला है उसमें मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के 120 प्रभावित लोगों को भी यह राशि मिली है।

श्री बी.एस.द्वारा....जारी

02.09.2024/1625/बी.एस./.एच के-1

श्री सुदर्शन सिंह बबलू जारी...

मेरी चिन्तपुरनी विधान सभा के अन्दर लगभग 120 लोग इस दायरे के अन्दर आए और उन्हें पैसा दिया गया। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि उस समय आनन-फानन में ऐसे लोगों को जल्दबाजी में पटवारी से रिपोर्ट मांगी गई और लोग पटवारी के पास नहीं पाहुंच पाए और रिपोर्ट बनाई भी गई तो वह समय पर इसे जमा नहीं करवा पाए। वे लोग आपदा के दायरे में नहीं आ पाए और उन लोगों को उस चीज का फायदा नहीं मिल पाया। हमने भी उन लोगों के घरों में जा करके देखा है और अलग-अलग पंचायतों में जा करके देखा है वे सब में राहत राशि के हकदार हैं परंतु जो राहत राशि मुख्य मंत्री जी ने दी है, उससे वे लोग वंचित रहे हैं। मैं सदन के माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसका फिर से सर्वे करवाने की कृपा करें और सच में जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको इस बजट का फायदा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अजय सोलंकी जी ने बात रखी है कि हमारे पास बहुत से केसिज ऐसे आते हैं कि जिन लोगों के घरों को खतरा बना हुआ है परंतु हम अपनी निधि से उन घरों के डंगों के लिए पैसे नहीं दे सकते और प्रदेश में ऐसे घर हैं जो ऊंची जगहों पर हैं और बारिश में उन घरों को गिरने का खतरा रहता है और उन लोगों की वास्तव में समस्या बनी है परंतु हम लोग उनकी कुछ भी सहायता नहीं कर पाते। उन लोगों को डंगों के लिए राहत राशि न भी दी जाए परंतु जिन लोगों के मकान गिरने वाले हैं यदि पटवारी उनकी सही रिपोर्ट देता है तो उन्हें राहत हेतु

कुछ पैसा दिया जाए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पिछली वर्ष जब आपदा आई तो मेरा चुनाव क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में एक कटोहड कलां पंचायत आती है वह स्वां नदी के बिल्कुल किनारे पर है। जब स्वां नदी में पिछली वर्ष बाढ़ आई तो उसका तटीयकरण ढह गया था। मैंने मुख्य मंत्री जी के समक्ष यह बात भी रखी थी और एक हमारी नगर पंचायत अंब है वहां भी एक छोटा सा नाला था जिसके तटीयकरण करने के लिए मुख्य मंत्री जी ने मैंने अनुरोध किया था। मैं धन्यवाद करूंगा मुख्य मंत्री जी का कि इन्होंने 7.50 करोड़ रुपये नगर पंचायत अंब के नाले के लिए स्वीकृत किए हैं। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं। मेरी कटोहड कलां पंचायत है उसका तटीयकरण बह गया है और उसकी विभाग ने रिपेयर कर दी थी। इस बार निचले क्षेत्रों में बरसात कम हुई है परंतु बरसात ज्यादा हो जाती तो हमारी चार पंचायतें जो उस क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं उनमें

02.09.2024/1625/बी.एस./.एच के-2

भारी नुकसान हो जाता। मैंने मुख्य मंत्री जी से इसके लिए निवेदन किया है और मुझे आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही इस समस्या का हल करेंगे। इसके अलावा पोलिया परोहतां पंचायत है वहां पर भी भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा जवार पंचायत के अन्तर्गत पन्गलू गांव आता है जहां पर आपदा के चलते काफी मकान बह गए थे और वहां के लोगों की जमीन रहने के लायक नहीं है। मैं इस सदन के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि उन लोगों का एक सर्वे करके उन्हें घर बनाने के लिए कहीं बाहर जमीन दी जाए। अगर वहां पर दोबारा से मकान बना भी दिए जाएं तो भी वह जगह रहने के लायक नहीं है। उस जमीन में पत्थर और मिट्टी ज्यादा मिक्स है और जब भी पानी आता है तो वहां पर बहुत बड़ा लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। आज से तीन साल पहले जो भारी बारिश हुई थी उसके चलते कई लोगों के घर आज भी खतरे में है। मैं निवेदन करूंगा कि जब जवार पंचायत का पन्गलू गांव है उन लोगों के लिए थोड़ी-थोड़ी जमीन बाहर दी जाए ताकि वे लोग रहने के लिए अपना घर बना सकें। इसके अलावा बेहड़ जसवां पंचायत है और टकारला पंचायत है पिछली बरसात के चलते किसानों की आलू और मक्की की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। मेरी हमोली पंचायत है वहां पर भी आपदा के चलते आलू की फसल

का किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। उसके लिए भी मैंने कृषि मंत्री जी से बात की थी और पटवारी की रिपार्ट भी हमने जमा करवा दी है। मैं मुख्य मंत्री जी से और कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जल्द-से-जल्द की जाए। इसके अलावा हमारी गिन्दपुर मलोण पंचायत में भी बरसात के चलते रास्ते बंद हो गए थे परंतु मैं लोक निर्माण विभाग का धन्यवाद करूंगा कि वहां पर रास्ते समय पर खोल दिए थे। मैं चाहता हूं कि फिर से मेरे चुनाव क्षेत्र में सर्वे किया जाए ताकि जो लोग राहत राशि से बचे हैं उन्हें इसका लाभ मिल सके और जिन लोगों के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

02.09.2024/1630/डी0टी0/वाई0के0-1

श्री सुदर्शन सिंह बबलू जारी...

उन्हें जमीन दी जाए और जिनके मकान गिर गये हैं उनके लिए जो पैकेज माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दिया गया है उसमें उन लोगों को भी शमिल किया जाये। मैं ये भी आग्रह करना चाहूंगा कि उन लोगों के लिए पटवारी की रिपोर्ट पुनः लेकर रिसर्वे करवाया जाये।

ये प्रस्ताव हमारे विपक्ष के साथियों द्वारा यहां लाया गया। उनके द्वारा इस पर बड़ी-बड़ी बातें कहीं गई लेकिन जब इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात थी तब भी ये सदन से भाग गये थे और आज भी ये इस सदन में चले गये हैं। आज मानसून सत्र की ये पांचवी बैठक है और आज पांच दिनों में जैसा विपक्ष के साथी यहां व्यवहार कर रहें हैं उससे पता चलता है कि वह प्रदेश की जनता के मुद्दों के प्रति कितने गम्भीर हैं। मैंने जो गुजारिश इस सदन में की है सरकार उसकी ओर जरूर ध्यान दे।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने लड़कियों के विवाह की आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया है, ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया गया है, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी को बधाई देता हूं और हम इसकी प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि इस कानून को अगर छः माह के बाद इंम्पलीमेंट किया जाये तो अच्छा होगा क्योंकि कई लोगों ने अपनी बेटियों

की शादी, जिनकी आयु अभी 21 वर्ष नहीं हुई है, रख दी और वे विवाह की सारी तैयारियां भी कर चुके हैं अगर इस कानून को छः माह डिले से लागू किया जायेगा तो उनको राहत मिलेगी क्योंकि वर्तमान में उनको इस कानून के पास होने की ख़बर को सुन कर परेशनी हो रही है। इस संबंध में काफी लोगों मेरे पास भी आये। अगर ये कानून शीघ्र लागू हो जाता है तो वे अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते और उनका काफी पैसाी बरबाद हो जायेगा और अगर वे अपनी बेटी की शादी कर लेते हैं तो वे शादी पंजीकृत नहीं होगी। इसलिए मैं बार-बार आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि मेरी प्रार्थना पर जरूर विचार-विमर्श किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्षः अब माननीय राजस्व मंत्री महोदय इस चर्चा का उत्तर देंगे। मैं आग्रह करूंगा माननीय राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी कि वे चर्चा का उत्तर दें और माननीय मंत्री जी उत्तर के उपरांत चर्चा समाप्त हो जायेगी।

02.09.2024/1630/डी0टी0/वाई0के0-2

राजस्व मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव नियम-130 के अंतर्गत 27 अगस्त को यहां लाया गया। लगभग 4 दिनों में एक मैराथन डिबेट इस विषय पर इस मान्य सदन में हुई। हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर, सर्व श्री चंद्र शेखर, सुश्री अनुराधा राणा, श्री लोकेन्द्र कुमार और श्री सुरेन्द्र शौरी जी ने प्रस्ताव रखा था "प्रदेश में भारी बरसात/आपदा के कारण जनमानस, सड़कों, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि, पेयजल योजना व सिंचाई योजनाओं को हुए नुकसान बारे ये सदन विचार करे"। इस प्रस्ताव में 30 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और करीब 39 घंटे से ज्यादा का समय इस विषय की चर्चा पर लगा। परंतु मैं इसे एक विचित्र घटना ही कहूंगा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जो इस प्रस्ताव के सूत्रधार थे क्योंकि उनका नाम पहले रखा गया था वह इस समय सदन में उपस्थित नहीं है। आज जब उत्तर सुनने की बारी थी तो वह चले गये। उन्होंने अपनी कही और अपने विपक्ष के अन्य माननीय सदस्यों को अपने साथ लेकर चले गये। ये सबसे बड़ी विडम्बना है कि नेता प्रतिपक्ष ऐसे हो गये हैं कि वे

अपनी बात तो रख देते हैं लेकिन दूसरों को बोलने भी नहीं देते और दूसरे की सुनते भी नहीं हैं। जब प्रश्नकाल होता है उसमें जिस माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा होता है उसे ही अनुपूरक प्रश्न पूछने का पहला अधिकारी होता है। परंतु श्री जय राम जी बीच में खड़े हो जाते हैं और जो माननीय सदस्य चाहे वे उनके पक्ष के भी हैं, जिन्होंने प्रश्न लगाया है, उनको भी अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका नहीं देते। जहां तक अन्य चर्चाओं की बात है उसमें तो वो किसी को मौका देते ही नहीं।

अध्यक्षः माननीय राजस्व मंत्री जी, अब तो उनका ये भी प्रयास है कि अध्यक्ष भी कुछ न बोले।

राजस्व मंत्री श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

02-09-2024/1635/वाई.के.-एन.जी/1

अध्यक्ष के पश्चात.....

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने सही फरमाया है कि अब विपक्ष के लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी मूकदर्शक बना दिया जाए। ताकि श्री जय राम ठाकुर जी ही यहां पर बोल सकें क्योंकि बाकियों की तो वे सुनते ही नहीं हैं। यह ठीक है कि विपक्ष के लोग किसी-किसी मुद्दे को लेकर माननीय सदन से बाहर चले गए। आप सभी देख ही रहे हैं कि विपक्ष की ओर से जो वॉक्आऊट हो रहा था वह पूर्ण रूप से था ही नहीं क्योंकि श्री जय राम ठाकुर जी अपने माननीय सदस्यों से बाहर जाने के लिए कहते थे तो कुछ माननीय सदस्य यहीं पर बैठे रहते थे। इसका मतलब यह था कि इनका वॉक्आऊट कम्पलीट नहीं था और इनके माननीय सदस्य नहीं चाहते कि वे वॉक्आऊट करें। हम लोग ऐसी सास तो नहीं हैं कि बार-बार बहू को रूठवाएं। विपक्ष के लोग तो रूठ कर इतनी बार मायके भाग रहे हैं कि अब मायके में भी जगह नहीं बची होगी। श्री जय राम ठाकुर जी ने इस तरह की एक प्रथा चला दी है कि ये किसी की सुनते ही नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्यों ने बहुत गम्भीरता से अपने-अपने विचार रखे हैं। माननीय सदस्यों ने अपने चुनाव क्षेत्र में भारी बरसात के कारण पिछले और इस वर्ष

जो आपदा आई है उससे हुए नुकसान के बारे में विस्तार से अपनी बात को रखा है। ज्यादातर सदस्यों ने आपदा प्रबंधन को लेकर हुए काम की प्रशंसा की है। इसके अलावा प्रतिपक्ष के लोगों ने भी आपदा प्रबंधन में किसी प्रकार की नुख्ताचीनी नहीं की है। उन्होंने केवल छुट-पुट समस्याएं, थोड़े से लोग राहत से छूट गए या उनके हिसाब से जिन लोगों को समय पर सहायता नहीं मिल पाई, उसके बारे में ही बात की है। मैं पक्ष व विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और हमारे विभाग के अधिकारियों ने प्रत्येक माननीय सदस्य के सुझाव व कमियों को नोट कर लिया है। मैं माननीय सदन को आश्वस्त करता हूं कि आपदा प्रबंधन में हमारी सरकार आज तक जो नहीं हुआ उसे करने जा रही है।

02-09-2024/1635/वाई.के.-एन.जी/2

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि यदि वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन कानून नहीं आया होता तो आज केन्द्र सरकार ने जिस प्रकार से हमारे साथ बर्ताव किया है, उससे हम कहीं के नहीं रहते। मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि Disaster Management Act, NDRF and SDRF बना ये सभी कांग्रेस विचारधारा की ही सोच है। इसी दौरान अन्य बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं, जैसे सूचना का अधिकार, मनरेगा, Food Security Act वर्ष 2013 में आया और इसके अलावा Forest Rights Act (FRA), 2006 भी कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में आया था। Forest Rights Act का सबसे बड़ा फायदा जनजाति क्षेत्र और परम्परागत Forest Dwellers को मिला है। इसी प्रकार शिक्षा का अधिकार कानून भी उसी दौरान लाया गया। ये सभी कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में आए हैं और इनमें भाजपा का किसी भी प्रकार का योगदान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, हमें विधी ने बहुत कुछ दिया है। सुःख के साथ गम भी दिया है। प्रकृति ने भी हमें बहुत सारे उपहार दिए हैं और उपहार के साथ-साथ आपदाएं भी दी हैं। हमारा हिमाचल प्रदेश बहुत खूबसूरत है। जो लोग विदेशों व स्विट्ज़रलैंड में गए हैं, वे कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश भी उन देशों से कम नहीं है। इस खूबसूरत धरती पर हमारे

ऊंचे हिमालय 12 माह बर्फ से ढ़के रहते हैं। निचले इलाकों में धौलाधार की पहाड़ियां व प्लेन इलाके हैं। इन सभी इलाकों में हमें अलग-अलग प्रकार की आपदाओं से जूझना पड़ता है। हमारे प्रदेश में तो आपदाएं भी अनेक प्रकार की हो गई हैं। मेरे साथियों ने अभी कहा कि यहां पर प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदा तो आती ही थी लेकिन इन आपदाओं के अलावा इस वर्ष एक अन्य आपदा भी प्रदेश में आई थी। वह आपदा भाजपा की ओर से तैयार की गई थी। वह ई.डी. और सी.बी.आई. वाली आपदा है। पैसों के द्वारा दल बदलने की आपदा है। इन अपदाओं के कारण हमारे विकास के बहुत सारे काम रुक जाते हैं। बहुत सारे लोग बेकार हो जाते हैं और बार-बार चुनाव की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसमें धन की भी बहुत बर्बादी होती है। हमारे नैतिक मूल्यों को भी लगातार गिराया जाता है।

02-09-2024/1635/वाई.के.-एन.जी/3

पूर्व में आयाराम-गयाराम का जमाना होता था और अब भाजपा ने फिर से वही बना दिया है। भाजपा व मोदी जी ने ठान लिया है कि जनता द्वारा चाहे किसी की भी सरकार चुनी जाए लेकिन सरकार तो भाजपा की ही बनेगी। चुनावों में चाहे कांग्रेस जीते, चाहे एस.पी. जीते या चाहे अन्य कोई भी पार्टी जीते लेकिन बाद में तो सरकार भाजपा की ही बनेगी।

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

02.09.2024/1640/केएस/एजी/1

राजस्व मंत्री जारी--

हिमाचल में यह अलग बात है कि प्राकृतिक आपदा के साथ-साथ ये राजनीतिक आपदा भी ले कर आए। इतना पैसा जो हमें आपदा में मिल सकता था, उतना इन्होंने विधायकों को खरीदने में लगा दिया फिर भी बेशर्मी की तरह यहां छाती तान कर कहते हैं कि हम ये कर गए, वो कर गए। मेरे बहुत सारे साथी यहां पर जय राम जी को कहते हैं कि हमारे साथ दिल्ली चलो, केंद्र से कुछ पैसा ले कर आएंगे। अरे, आप इनसे मदद मांग रहे हो जो अपनी

मदद नहीं कर सके। जब इनकी डबल इंजन की सरकार थी, उस समय ये अपनी मदद नहीं कर सके। मोदी जी इनकी नहीं सुनते थे। अब तो दिल्ली का इंजन भी अभी से हांफने लगा है। इनके पास तो इंजन भी नहीं है। तो जो मेरे साथी जय राम जी को दिल्ली जाने के लिए बार-बार कहते हैं, इनको कहने की बजाय आप अपने तरीके से प्रयत्न करो, जय राम जी तो ठन-ठन गोपाल हैं, इनके पास कुछ भी मिलने वाला नहीं।

अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदाओं में सबसे खतरनाक भूकंप है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एवलांच है, भू-स्खलन है, बाढ़ व भारी वर्षा है, ओले हैं, समुद्री तुफान है, बवंडर है, आसमानी बिजली गिरना तथा बादल फटना है जो आजकल सबसे ज्यादा फट रहे हैं। इसके अलावा अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी हैं। बहुत सारे साथियों ने चिंता व्यक्त की कि इन आपदाओं से कैसे पूर्वानुमान लगाया जाए। आज के हमारे विज्ञान में बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं का अनुमान लगाना सम्भव है परंतु जो बड़ी आपदाएं हैं, खासकर भूकंप या बिजली फटने की घटना है, इसमें हम अभी इतना विकसित नहीं हो पाए हैं। अब आर्टिफिशियल इंटैलिजैंस का जमाना आ गया है, एक समय होगा कि हम पिन प्वाइंट कर सकेंगे कि फ्लां जगह पर बादल फटने वाला है। उससे और चीजें नहीं तो कम से कम हम लोगों की जान तो बचा सकेंगे जो कि आने वाले समय में हो सकता है। इसकी तरफ हमारी सरकार भी बैठी हुई नहीं है। हर तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट को एक लेटैस्ट टैक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। यह अलग बात है कि हमारे देश में प्रधान मंत्री इतने अवैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि जब बादल होता है तो उसके अंदर से राडार की तरंगे नहीं जाती इसलिए उन्होंने कहा कि मौसम खराब है, सर्जिकल स्ट्राइक कर दो। टॉप पर बैठे हुए लोग ऐसी बात करते हैं कि नाले से गैस बना देंगे, इस किस्म की अवैज्ञानिक बात करते हैं और सबसे

बड़ी बात तो यह है कि कोरोना के समय उन्होंने कहा कि थाली और घंटी बजाओ और हमने थाली और घंटी बजा दी। अभी हिमाचल को भी उन्होंने यही कहा कि थाली और घंटी बजाओ और आपदा से निपट लो। यही बात कर रहे हैं। आज जय राम जी नहीं है और हमें कुछ बोलने का मज़ा भी नहीं आ रहा है। अगर जय राम जी होते तो ऊपर जो केंद्र में इनके

वैज्ञानिक लोग बैठे हैं, ऐसे-ऐसे भगवान बैठे हैं, उनके बारे में जय राम जी को सुनाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय, जो मानव निर्मित आपदा है, वह भी कम नहीं है। अभी लोक निर्माण मंत्री यहां कह रहे थे कि जो सड़क निर्माण है, खासकर जो अभी फोरलेन और नेशनल हाईवे बने हैं या जो हम भी रोड बना रहे हैं, हम वैज्ञानिक तरीके से सड़क नहीं बनाते। हम ब्लास्टिंग करते हैं, बिना स्लोप को देखे करते हैं और जब बरसात होती है तो बहुत नुकसान हो जाता है। सारा का सारा हमारा कालका से शिमला का फोरलेन बनते हुए पता नहीं कितने साल हो गए। वहां पैसे लिए जा रहे हैं, टोल टैक्स लिया जा रहा है जबकि रोड एक ही साइड है। फोरलेन में तो हम जा ही नहीं रहे हैं। बीच-बीच में कई बार हम फोर लेन समझ कर जा रहे होते हैं, एकदम से वह डबल लेन हो जाता है और सामने से गाड़ी आ जाती है जिसकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हमें सड़क निर्माण को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। यहां पर हमारे जो भवन बन रहे हैं, वे कैसे बना रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा नुकसान निचले क्षेत्रों में हो रहा है जो हमारे डैम बने हुए हैं, उनमें बिना वार्निंग दिए पानी छोड़ा जाता है। उसमें जो इतना पानी भर जाता है, उसको क्यों भराया जाता है? एक लिमिट के बाद उसको छोड़ना चाहिए। हमारा एक डैम सेफ्टी एक्ट है जिसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं गया है। अब हमें इस एक्ट को भी लागू करने की ज़रूरत है। जब पौंग डैम में पानी जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो उसको एकदम से छोड़ते हैं और निचले इलाकों में सारे के सारे मकान बह जाते हैं और लोगों की जान चली जाती है। तो इनके ऊपर भी एक्शन लेना पड़ेगा।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

02.09.2024/1645/av/ag/1

राजस्व मंत्री --------जारी

डैम्ज में उतना ही पानी रखना पड़ेगा जितनी कि नीचे के इलाकों में उसकी निकासी हो सके। अन्यथा एकदम छोड़ने पर पानी से नीचे के क्षेत्र तबाह हो जाते हैं जिसके लिए इनके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। इसलिए हम डैम सेफ्टी ऐक्ट को आपदा प्रबंधन के द्वारा

एनफोर्स करेंगे ताकि इस प्रकार की घटना बार-बार न हो। इसके अतिरिक्त हम बहुत सारे दूसरे काम भी कर रहे हैं, जैसे जंगलों का अनसाईंटिफिक तरीके से कटान हो रहा है। उसके कारण सारे-के-सारे नाले खाली हो गए हैं और पानी उन्हीं नालों से बह कर जाता है। यहां पर वर्ष 2023 में जो प्राकृतिक आपदाएं घटी हैं वे सचमुच में अपने आप में बहुत बड़े स्केल पर घटी थीं। अगर हिसाब लगाया जाए तो उस दौरान लगभग 12 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। अगर लोगों की गौशालाएं और कच्चे-पक्के मकान इत्यादि सभी चीजों का जायजा लिया जाए तो लगभग 24 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। इसके अतिरिक्त हजारों बीघा जमीन बह गई यानी सब मिलाकर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह हुई कि हमारी सरकार ने जिस-जिस जगह पर आपदाएं आईं वहां पर तुरंत रिस्पोंड किया। आपदा में सबसे बड़ा काम यही होता है कि हम पीड़ितों को कितने समय में राहत दे सकते हैं। अगर अभी कहीं पर बादल फटा और वहां पर आप दो दिन बाद पहुंच रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं (***) ये

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

02.09.2024/1645/av/ag/2

लोग यहां पर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। हम यहां पर कहना नहीं चाहते कि हमारे मुख्य मंत्री जी और मंत्री गण ने आपदा के दौरान रात के दो-दो बजे तक लोगों की मदद की है। परंतु यहां पर एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि मैं वहां गया था और दो घंटे पैदल चला। अगर मैं बताऊं तो मैं 14 हजार फीट की ऊंचाई पर गया था और मैं तो डाइबिटिक हूं। मैंने तो 14 हजार फीट की ऊंचाई पर जाकर अपनी जान को जोखिम में डाला था परंतु मैंने इसका बखान कभी नहीं किया। परंतु जब ये लोग यहां पर अपने दो-दो घंटे की बात कहते हैं तो हमसे भी अपनी बात बताने से नहीं रह जाता। इस प्राकृतिक आपदा में चाहे वे हमारे होम गार्ड के जवान थे, चाहे पुलिस जवान, आई0टी0बी0पी0, सेना के लोग, एयर फोर्स के लोग, बिजली बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारी, स्थानीय लोग, एस0जे0बी0एन0एल0, राजस्व

विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग इत्यादि कोई भी विभाग ऐसा नहीं था जिसने आपदा के दौरान अपना कुछ-न-कुछ सहयोग न दिया हो। इस आपदा के दौरान जिन लोगों ने अपनी जान दांव पर लगाकर प्रभावित लोगों को तुरंत राहत पहुंचाई उनको उत्साहित करने हेतु विपक्ष की ओर से एक शब्द भी नहीं निकलता। उलटा यहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो वक्तव्य दिया उससे अपने लोगों को और मुसीबत में डाल दिया। वे यहां पर 6-7 लोगों के नाम ले रहे थे कि इनको-इनको नहीं मिला। मैंने जब उसकी पूरी छानबीन की तो वे सारे-के-सारे एनक्रोचर्ज निकले। अब उनका नम्बर लगेगा क्योंकि हाई कोर्ट ने तो रोज़ केस लगाए हुए हैं। वे चुपचाप से रहते तो कोई एनक्रोचर डिटैक्ट नहीं होना था।

टी सी द्वारा जारी

02.09.2024/1650/टी0सी0वी0/ए0एस0-1
माननीय राजस्व मंत्री.... जारी

अब तो वे नोटिस में आ गए हैं और वे अब श्री जय राम ठाकुर जी को जिंदगी भर कोसेंगे क्योंकि वे बेचारे मारे गए। इस तरह की बातें करके हम लोगों को मुश्किल में डाल रहे हैं। हमें यह देखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आपदा प्रबंधन किया गया उसमें सभी लोगों ने अपनी जान लगाकर पिछली बार और इस बार भी समय को गंवाएं बगैर काम किया। हम भी इस माननीय सदन में इस मामले को उठाते थे कि रलीफ मैनुअल की राशि को बढ़ाया जाए क्योंकि यह बहुत कम है परंतु किसी भी सरकार के समय में किसी ने भी इसको बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। मैं माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस पीड़ा को समझा और वित्तीय संसाधन न होते हुए भी सात लाख रुपये दिए हैं। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है और ऐसा पूरे हिन्दुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। हिन्दुस्तान में हिमाचल प्रदेश से भी ज्यादा संसाधनों वाले राज्य हैं जिनके पास सरप्लस बजट हैं लेकिन वे भी ऐसा नहीं कर पाए। यह सिर्फ मकानों के लिए ही नहीं हुआ, बल्कि गऊशाला के लिए 50 हजार रुपये दिए गए। पहले आंशिक डेमेज के लिए 1200 रुपये मिलते थे,

उनको एक लाख रुपये मिले। आपदा में बड़े पशुओं की मृत्यु हो जाने पर पहले 35 हजार रुपये मिलता था लेकिन उसको 55 हजार रुपये दिए गए। तीन भेड़ों के लिए केवल 3 हजार रुपये मिलते थे परंतु अब जितनी भेड़ों का नुकसान हुआ उनके एवज़ में 6 हजार रुपये प्रति भेड़ दिया गया। लोगों को इतना बढ़िया पैकेज मिला लेकिन श्री जय राम ठाकुर जी के मुख से इसके बारे में एक शब्द भी नहीं निकला कि यह अच्छा काम हुआ है। ये बोलते क्या है यह समझ ही नहीं आता है? आज आपने देखा होगा कि इन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। इनके हिसाब से तो यह बहुत सनसीनीखेज मुद्दा था कि वित्तीय संसाधन और वित्तीय संकट को लेकर नियम-67 के अंतर्गत मुद्दा उठाएंगे परंतु ऐसा नहीं हो पाया। श्री जय राम ठाकुर जी के साथ श्री विपिन सिंह परमार जी बैठते हैं और श्री परमार जी को उन्होंने कांफिडेंस में नहीं लिया होगा तथा वे प्रश्नकाल में ही खड़े हो गए। अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था दी कि अभी प्रश्नकाल है और प्वाइंट ऑफ ऑर्डर का विषय बाद में उठा लेना। इनको नियम-67 के तहत विषय को उठाना चाहिए था कि सारे काम रोक कर हमारी बात को सुना जाए परंतु वे इस बात को छोड़कर श्री विपिन सिंह परमार जी की बात में आ गए और उसी बात को

लेकर वाकआउट कर गए। इनके बीच में तालमेल की ही कमी नहीं है बल्कि दिमाग के संतुलन की भी कमी हो गई है। श्री जय राम ठाकुर जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा षड़यंत्र किया और 150 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसे खर्च किए। ई0डी0 और सी0बी0आई0 से लेकर दिल्ली से प्रधान मंत्री मोदी जी और श्री नड्डा जी का आशीर्वाद लेकर आए थे। इसके अलावा हमारे जयचन्दों का भी इन्हें आशीर्वाद मिला था लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वे कुछ नहीं कर पाए और हम फिर से 40 पर आ गए। मुझे चिन्ता है कि इनको कुछ हो न जाए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इनको कुछ बड़ा हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि कहीं कुछ और बोलना शुरू न कर दें। ये तो नींद में भी हररोज बोलते थे कि सरकार गिरी गई, सरकार गिर गई और लॉस्ट में तो कह रहे थे कि हमें भगवान ने भी नहीं बचाया। अब पता नहीं ये क्या करेंगे? हां, चुनाव के समय में ये कई जगह जरूर गिरे। यह आपको पता ही है कि आगे कौन लोग थे? यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह भी पता है कि ये किसके पीछे-पीछे चलते हुए

गिरे थे? आपदा प्रबंधन के लिए भी हमारी सरकार बहुत चिंतित है और हमने इसके ऊपर भी काम करना शुरू किया है। इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत काम कर रहे हैं । एस0डी0आर0एफ0 में केवल 129 लोग हैं। अब उसको बढ़ाने की बात हो रही है। उसमें पुलिस के बजाय हम होम गार्ड के नौजवानों को भर्ती करके एक ऐसी फोर्स बनाना चाहते हैं जो हिमाचल प्रदेश में आपदा के समय हमेशा तैयार रहे। उनको सरकार की ओर से बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाएगी और बेहतरीन उपकरण भी मुहैया करवाए जाएंगे। उनको पूरे हिमाचल में ऐसी स्टैटिक जगह पर पहले ही तैनात करके रखेंगे। इनको पण्डोह में भी रखा जाएगा। यदि कांगड़ा में कहीं कोई प्रोब्लम हो गई तो उनको वहां से लाया जाएगा लेकिन इसमें समय की बर्बादी होती है। इसलिए जो-जो भी डिजास्टर प्रोन एरियाज हैं वहां पर इस टीमों को रखा जाएगा। इसके साथ ही हमारी हर पंचायत लैवल पर आपदा मित्र बनाने की एक स्कीम है उसको भी हम धरातल पर उतारेंगे।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

2-09-2024/1655/एन0एस0-ए0एस0/1

राजस्व मंत्री ----- जारी

हर गांव में कम-से-कम 10 वालंटियर्ज को ट्रेंड करेंगे। पंचायत घरों में बेसिक मिनिमम जो इक्विपमेंट होता है जिसमें फर्स्ट एड का सामान रख दिया, कुछ क्लाइंबिंग रोप्स या स्ट्रेचिज होते हैं, ऐसे-ऐसे उपकरणों को पंचायत घरों में रखेंगे ताकि उस गांव या वहां के नजदीक किसी गांव में घटना घटी तो राहत मित्र उस गांव में जाकर सहायता कर सकें। उनको ट्रेनिंग देकर रखेंगे ताकि जितने में बड़ी टीमें आएंगी तब तक लोगों को तुरंत राहत पहुंचा सकें। हमें तहसील स्तर पर, सब-डिवीजन स्तर पर और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने की जरूरत है। अभी हम बहुत-सा डेमोंसट्रेशन करते हैं कि आपदा आएगी तो ऐसा करना है। मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। उसमें पैसे ही खर्च होते हैं। हमें डेमोंसट्रेशन के बजाए इसको हकीकत में बदलने की जरूरत है। हमें लोगों को ट्रेंड करने की जरूरत है। अगर हर जगह लोग ट्रेंड होंगे तो हमारे पास हर जगह पर फोर्स होगी और हम ज्यादा लोगों की जान बचा सकते हैं तथा लोगों का जो भी नुकसान हो रहा है उसको कम किया जा सकता है। इसके लिए हमें कोशिश करने की जरूरत है। आने वाले समय में,

मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपदा प्रबंधन में हम इंडिया में नम्बर वन पर बन जाएंगे। हम खाली मुंह से नहीं बोल रहे हैं। हम करके दिखाएंगे और हमने करके दिखाया है। अभी समेज के अंदर 34 लोगों की जान चली गई। मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे अधिकारियों ने चाहे वे डी0सी0 लैवल पर थे, चाहे एस0डी0एम0 लैवल पर थे, चाहे वे एस0पी0 लैवल पर थे या फिर चाहे शिमला या रामपुर से गए, जैसे ही उनको पता चला वे बिना समय गंवाएं तुरंत मौके पर पहुंचे हैं। वहां पर एस0जे0वी0एन0एल0 के लोग थे उन्होंने सी0आर0पी0एफ0 और सी0आई0एस0एफ0 के लोगों को तुरंत डेप्लॉय किया और काम शुरू किया। उसी दिन मुख्य मंत्री जी ने ओक ओवर में सुबह 6.00 बजे मीटिंग रखी, दिन में अधिकारियों के साथ हाई लैवल की मीटिंग की। उस दिन हेलिकाप्टर यहां से उड़ नहीं पाया नहीं तो मुख्य मंत्री जी उसी दिन वहां पहुंच जाते। परंतु हम वहां पर पहुंचे। समेज और बागीपुल में 9 लोगों की जान चली गई। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमने रिकॉर्ड समय में बागीपुल और उसके साथ लगते दो और पुल यानी कुल तीन पुल 14 दिनों के अंदर वहां पर बैली ब्रिजिज लगाए जो 60-60 मीटर के थे। आज तक इतनी स्पीड में काम नहीं हुआ। वहां पर लोग नाले के आर-पार फंसे हुए थे और वे आर-पार

2-09-2024/1655/एन0एस0-ए0एस0/2

नहीं आ सकते थे। हमने रिकॉर्ड समय में लोक निर्माण विभाग से एक दिन के अंदर आदमी चलने वाला झूला बनवाया। मैं इस विभाग का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने एक दिन के अंदर वहां पर फुट ब्रिज बना कर रिकॉर्ड कायम किया जिसके लिए लोग कहते थे कि यह दस दिनों तक नहीं बनेगा। आपदा का प्रबंधन इस हिसाब से होना चाहिए। हम लोग रात को समेज पहुंचे। वहां पर हमारी सारी टीमें लगी हुई थीं। एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, आई0टी0बी0पी0, सी0आई0एस0एफ0, पुलिस और होम गार्ड आदि सबने कोशिश की। लगातार एक हफ्ते तक 8 जे0सी0बी0 लगी रहीं। लोगों की भावनाओं का हमने ध्यान रखा। हमें पता था कि इतना मलबा आया है कि लाशें वहां नहीं होंगी लेकिन लोगों का कहना था कि लाशें वहीं हैं। वहां पर 5-10 फुट धरती को खोदा गया परंतु लाशें वहां नहीं मिली और लाशें कई किलोमीटर नीचे जाकर मिलीं। किसी का कोई अंग मिला और किसी का कोई अंग मिला। हमने कहीं कमी नहीं रखी। रात को 9.00 बजे जो कुल्लू के 6 लोग थे जिनको यह शिकायत थी कि हमें कोई नहीं देख रहा है उनको भी 10,000 रुपये

रात को मिले तो उन्होंने भी राहत की सांस ली। आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने की जरूरत है। यहां पर मेरे साथी कह रहे थे कि मण्डी में कोई नहीं आया। यह गलत बात है। हमने एन0डी0आर0एफ0 और एयर फोर्स को रिक्विजिशन भेजी थी और मौसम खराब होने के कारण एयर फोर्स वाले नहीं आए तो हमारे एन0डी0आर0एफ0 के लोग वहां पर पहुंचे और उसके बाद जिलाधीश महोदय वहां पर पहुंचे तथा दूसरे अधिकारी भी वहां पर पहुंचे। वहां पर एक-एक परिवार को पैसा दिया गया। एक-एक को राहत राशि दी गई और जो भी वहां पर नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए कोशिश की जा रही है। इसी तरह जो होशियारपुर के एरिया में हुआ। आज उसका प्रश्न यहां पर लगा था लेकिन विपक्ष यहां पर मौजूद ही नहीं था। ये कह रह थे कि कोई पैसा नहीं मिला। 9 लोगों की

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

02.09.2024/1700/RKS/DC-1

राजस्व मंत्री.... जारी

पंजाब के होशियारपुर इलाके में जो 9 लोगों की मृत्यु हुई है, हमारी सरकार ने वह मामला पंजाब सरकार के साथ उठाया और उन लोगों को जो 4-4 लाख रुपये मुआवजा मिलना था, वह उन्हें मिला। जो चार पीड़ित परिवार थे उन्हें रेडक्रॉस के माध्यम से भी थोड़ी-बहुत सहायता दी गई। मेरे विपक्ष के साथी यहां मौजूद नहीं है इसलिए मैं इन्हें ये आंकड़े बाइ-पोस्ट या ऐसे भी उपलब्ध करवा दूंगा। उन्होंने सारी बातें गलत कही हैं। श्री जय राम ठाकुर जी ने कहा कि सारे एनक्रोचमेंट में पकड़े जाएंगे। श्री विपिन सिंह परमार जी ने जिन 15 लोगों का जिक्र किया वे भी दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। हम किसी को जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। ये कह रहे थे कि लोगों को किराया नहीं मिला। जिन लोगों को किराया दिया गया उसकी हमारे पास गांववार लिस्ट है। सत्तापक्ष के साथियों ने जहां-जहां की बात की मैं उनको इसकी जानकारी लिखित में दे दूंगा। मैं विपक्ष के साथियों को भी यह सूचना उपलब्ध करवा दूंगा। श्री सुरेन्द्र शौरी जी ने जो मामला उठाया था, जब हमने उस मामले की तहकीकात की तो वह भी टोटल गलत निकला। सभी लोगों को राहत मिली है। मंडी जिला में मनरेगा के तहत पिछली बार 420 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि का प्रावधान किया

गया था जिसमें से 250 करोड़ रिलीज हो गये हैं। इस बार आपदा इतनी ज्यादा नहीं आई है फिर भी हमने मनरेगा में 420 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि स्वीकृति की है। मंडी जिला के 10 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मनरेगा के तहत 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जारी की गई है। हम लोगों के मकान के आगे डंगे लगा रहे हैं जोकि सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। चाइना की दीवार से ज्यादा लंबी दीवार लगाने का कार्य हमारी सरकार मण्डी में कर रही है। लेकिन मण्डी वाले कहते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं हुआ। यह सारी बातें रिकॉर्ड में हैं। श्री जय राम ठाकुर जी के चुनाव क्षेत्र में सिर्फ 20-25 लोगों का नुकसान हुआ था लेकिन हमने इनके निर्वाचन क्षेत्र के लिए 12 करोड़ रुपये रिलीज कर दिए हैं। हमने मकानों के लिए अलग से राशि जारी की है। अगर सनसनी या क्रिटिसिज्म के लिए ये मुद्दे उठाते हैं तो वे प्रदेशहित में नहीं हैं। ठीक है आप क्रिटिसिज्म भी कीजिए परंतु इस आपदा से निपटने के लिए अपने कुछ सुझाव भी तो दीजिए। जो वित्तीय संकट है उसमें मैं कहना चाहूंगा कि सभी सरकारें उधार लेकर चलती हैं। हमें मोदी जी कह रहे हैं कि बाकी प्रदेशों को तो पैकेज मिलेगा लेकिन

02.09.2024/1700/RKS/DC-2

हिमाचल प्रदेश को उधार लेकर काम चलाना होगा। यह लिखित में दिया है। यह सोचने की जरूरत है कि आज की तारीख में हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें क्या करने की आवश्यकता है? आपदाएं आएंगी, आपदा रुकने वाली नहीं हैं। बादल फटने की घटनाएं होती रहेंगी। आपदा मैन मेड नहीं है। जब मौसम गर्म होता है, बादल ऊपर जाते हैं और पानी की जो बूंद होती हैं अगर वे नीचे नहीं आती तो एक ही जगह सारे बादल बरस जाते हैं। इसमें तीन-चार साइंटिफिक तरीकों को भी ढूंढा जा रहा है। समेज खड्ड में सतलुज नदी से ज्यादा पानी आया। सतलुज नदी में 1200 क्यूबिक्स पानी था और समेज में आधे घंटे में 1500 क्यूबिक्स पानी आ गया। यह एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसे रोकने या पूर्व अनुमान लगाने के लिए हम सक्षम नहीं है। जिन विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों या लोगों ने इन आपदाओं से निपटने के लिए अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है, मैं उन सबको सलाम करता हूं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि एक पतला सा नौजवान जो शायद साढ़ पांच

फीट का भी नहीं था उसने चंद्रताल में जो लोग फंसे थे उनकी काफी मदद की। उस काली अंधेरी रात में अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो वे लोग सीधे खड्ड में पहुंचते। मैंन उस नौजवान को अपनी ऐच्छिक निधि से एक लाख रुपये पुरस्कार राशि के रूप में दिए। हमने 15 अगस्त को उसका सम्मान करना चाहा था परंतु वह 15 अगस्त को वहां नहीं आया। जो हमारे बोर्डर रोड ओर्गेनाइजेशन का जे.सी.बी. ओप्रेटर्ज था, वह हरियाणा से था वह 6 फुट से ज्यादा लंबा था, उसने भी रात के अंधेरे में हमारा पूरा सहयोग किया।

श्री बी.एस.द्वारा....जारी

02.09.2024/1705/बी.एस./ डी.सी-1

राजस्व मंत्री जारी...

उन्होंने भी रात के अंधेरे में काम किया और अपनी जान को जोखिम में डाला। परंतु यह जो सूखा नाम का लड़का था यह हमारा हीरो था। ऐसे हीरो हमारे किन्नौर में भी हैं। हमारी निगुलसरी का रोड अभी भी बंद हो रहा है। पिछली बार हम वहां पर 10 बार खड़े रहे और जो रोड दो-तीन महीनों तक नहीं खुलना था उसे हमने 10 दिन के अन्दर खोला। वहां पर एक नौजवान, एल.एन.टी. ऑपरेटर की पत्थर लगने से जान चली गई है। उसे भी हमने एक लाख रुपये की सहायता राशि दी है। उसके घर में कोई भी नहीं है केवल एक बुजुर्ग पिता हैं। अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग नारे लगा रहे हैं कि रोड खोलिए। यह कोई हलवा नहीं है कि जल्दी से खा लिया? लोग वहां जा नहीं रहे हैं एल.एन.टी. ऑपरेटर के परिवार वाले रो रहे हैं कि इन्हें वहां मत भेजिए। फिर भी लोग वहां पर हिम्मत करके रोड खोल रहे हैं। चीन की सीमा उससे ऊपर है स्पिति का यह इलाका है और वहां पर किन्नौर का कुछ ही एरिया लगता है। इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि लोग इतनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं उन्हें इसका इनाम मिलना चाहिए। मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट ने एक इनाम रखा था उसमें सभी लोगों को एक जैसा बना दिया गया। जो दफ्तर में बैठा हुआ है वह भी उत्कृष्ट इनाम ले रहा है और जो अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है और 14,000 की ऊंचाई पर काम कर रहा है उसको भी आप बराबर मान रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें अंतर तो देखना पड़ेगा। यदि सभी को एक बराबर कर दिया जाए वह भी ठीक नहीं है। लोग जो हिम्मत करके अपनी जान को

जोखिम में डालता है वह हतोत्साहित होता है। वह देखता है कि मेरा पड़ोसी जो दफ्तर में बैठा है और जिसने किया ही कुछ नहीं वह मेरे बराबर इनाम ले रहा है। ये चीजें सोचने वाली है। हम आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि ये बातें सही हों। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी-बड़ी हेकड़ी मारते हैं। मुझे याद है जब प्रदेश में आदरणीय धूमल जी की वर्ष 1998 में सरकार थी, वर्ष 1997 में हमारे किन्नौर में सतलुज नदी किसी खड्डु के कारण बाधित हो गई थी और तीन-चार किलोमीटर की वहां पर झील बन गई। लोगों को आने-जाने के लिए कोई भी सुवधिा नहीं थी। हमने बिलासपुर से पर्यटन की बोट मंगवा कर रोहतांग के रास्ते वहां पर बोट चलाई। सेना का राफ्ट रिवर सतलुज में चलाया। जिसे वे वहां पर चलाने के लिए तैयार नहीं थे। जब सड़क निर्माण हुआ तो उस छोटे से पैच

02.09.2024/1705/बी.एस./ डी.सी-2

को बनाने के लिए हमें छह महीने लग गए। वहां पर एक बड़ा बेली ब्रिज लगना था, ये कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज था या नहीं, परंतु वह हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा बेली ब्रिज था। वहां तक सड़क पहुंचाने के लिए आर्मी का स्पेशल मैकेनाइज्ड डिवीजन है उसने दो माह तक अपने क्षेत्र में उसकी प्रैक्टिस की और दो महीने से ज्यादा उसे लगाने में समय लग गया। एक अधिकारी की पत्थर लगने से मृत्यु हो गई। आदरणीय धूमल जी की सरकार का सबसे पहला कैलेडर वर्ष 1998 में छपा और लिखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 24 दिन में वांगतू, एशिया का सबसे बड़ा बेली ब्रिज तैयार कर दिया। इतना झूठ ये लोग बोलते हैं। मैं तो कई बार कह चुका हूं कि ये झूठ बोलते हैं। आदरणीय जय राम जी जब मुख्य मंत्री थे तो इनके समय में क्या होता था? कहीं पर कोई आपदा हो जाती थी तो 5-6 दिनों तक कोई भी नहीं मिलता था। आदरणीय धूमल जी के समय हमने आठ दिन तक बैठ करके 11,000 की ऊंचाई पर यांगतांग पर भूख हड़ताल की तब जा करके सड़कों को खोलने का कार्य हुआ। आदरणीय धूमल जी के समय हमारा किन्नौर का सारा सेब सड़ गया। परंतु पिछली बार इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में किसी भी बावान का सेब नहीं सड़ने दिया। हमारी 5,000 सड़कें प्रभावित हुईं, 5,000 से ज्यादा हमारी पानी और सिंचाई की योजनाएं प्रभावित हुईं और 6,000 के करीब बिजली

बोर्ड के डी.टी.आर. प्रभावित हुए। परंतु फिर भी हमनें तेजी से काम करके इन्हें ठीक किया। आप उस सयम क्या कर रहे थे? आप लोगों में सनसनी फैलाने के लिए फलों को नाले में फिंगवा रहे थे। उसका वीडियो भी वायरल करवाया गया कि ये सेब सड़ गया है। जब मैंने उसकी तहकीकता करवाई और मौके पर पुलिस तथा एस.डी.एम. को भेजा तो पता चला कि उसने सड़े हुए सेब फैंके। जब हमने उसके खिलाफ प्रदूषण बोर्ड के द्वारा कार्रवाई करने की कोशिश की तो वह आदमी माफी मांगने लगा। शायद शिक्षा मंत्री जी के इलाके का वह आदमी था। इस किस्म की घटनाएं भी हुई है। अभी समय भी ज्यादा हो गया है और हमारे साथी सामने होंगे तो इन्हें भी कुछ सुनाना पड़ेगा कि आपदा प्रबंधन क्या होता है।

अध्यक्ष : मंत्री जी, वे भी आपकी बात को सुन रहे हैं।

02.09.2024/1705/बी.एस./ डी.सी-3

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि हमारी कांग्रेस की सरकार, हमारे मुख्य मंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी के कुशल नेतृत्व में आपदा प्रबंधन को बेहतरीन तरीके से किया है। पिछली बार भी किया और इस बार भी किया है। इसलिए इन्हें आदरणीय शांता कुमार जी ने भी शाबाशी दी है वित्तायोग ने भी इन्हें शाबाशी दी है परंतु आदरणीय जय राम ठाकुर जी इन्हें शाबाशी पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं, धन्यवाद।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

02.09.2024/1710/DT/HK-1

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया है। मैं चंद्रताल की घटना के बारे में बताना चाहता हूं कि कि श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री

और श्री संजय अवस्थी, मुख्य संसदीय सचिव उस घटना स्थल पर रात के 2:00 बजे तक जागे हुए थे और सेटेलाइट फोन से फोन करके मुझे बताते हैं कि हम उस घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। यह सरकार का सबसे बेस्ट आपदा प्रबंधन था और समेज घटना स्थल में भी मंत्री जी 12 घंटे के भीतर उस घटना स्थल पर पहुंचे। पहले हम हेलीकॉप्टर के जरिए उस घटना स्थल पर जा रहे थे और मंत्री जी ने बोला कि मैं समेज के लिए निकलता हूं, हेलीकॉप्टर तो खराब मौसम में उड़ेगा नहीं । मंत्री जी सुबह 7:30 बजे ही आ गए कि मुख्य मंत्री जी चलो उठो और हमने उस घटना स्थल पर चलना है। मैं मंत्री जी की डेडीकेशन इसलिए दिखाना चाहता हूं कि मंत्री जी जब काम करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं और मंत्री जी ने उन प्रभावित परिवारों के लिए भी पूरे दिल से कार्य किया। हमारी सरकार में जहां मंत्री कार्यों को गंभीरता से लेते हैं, वहां पर विपक्ष के सदस्य सदन से वॉकआउट करके चले जाते हैं और वह प्रदेश हित के कार्यों को नहीं समझते। यहां मंत्री जी की व्यक्तिगत सराहना भी होनी चाहिए कि उन्होंने आपदा के समय बहुत अच्छा कार्य किया है। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब इस प्रस्ताव पर कोई मतदान नहीं होगा। मंत्री जी के उत्तर के साथ यह चर्चा समाप्त हुई। अब एक और विषय नियम-130 के अंतर्गत आज की लिस्ट ऑफ बिजनेस में लिस्टिड है। अब इस विषय को माननीय सदस्य, श्री त्रिलोक जम्वाल जी नियम-130 के अंतर्गत प्रस्तुत करेंगे और इसी विषय पर माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा, श्री सुखराम चौधरी और श्री राकेश जम्वाल सदस्यों की भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे सब माननीय सदस्य भी इस चर्चा में भाग ले सकते हैं। यह विषय इस प्रकार से है कि ‘‘प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था बारे यह सदन विचार करें’’। लेकिन यह सभी माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है। तो लगता है कि जो विषय माननीय सदस्यों ने दिया है वह इस विषय पर गंभीर भी नहीं है because of their absence the issue is dropped.

02.09.2024/1710/DT/HK-2

अब इस माननीय सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 3 सितम्बर, 2024 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला : 171004 **यशपाल शर्मा**
दिनांक : 02 सितम्बर, 2024 **सचिव**